

रीवा

08 अगस्त 2026

शनिवार



दैनिक

मीडिया ऑडिटर

रीवा, सतना एवं मनेन्द्रगढ़ से एक साथ प्रकाशित

: बीफ बॉस :

आतंकी पन्न् का दावा-
जालंधर के स्कूल में
फहराया खालिस्तानी



झंडा

जालंधर,एजेंसी। जालंधर के शाहकोट इलाके के तहत आने वाले सरकारी मिडिल स्कूल कोटला हेरा में दीवार और प्रिंसिपल के दफ्तर के बाहर खालिस्तानी झंडा फहराने का दावा किया गया है। प्रतिबाधित अलगाववादी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) के प्रमुख आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्न् ने एक वीडियो में यह दावा किया।

पन्न् ने यह भी कहा कि जिन लोगों पर लोहे की मुट्ठी से शासन किया गया हो, उन पर जबर्न स्वतंत्रता का जश्न नहीं थोपा जा सकता। स्मृष्ट ने घटना का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस मामले में एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। वहीं 15 अगस्त से ठीक पहले हुई इस घटना के बाद सुरक्षा

थाईलैंड में 9वीं के छात्र
ने स्कूल में फायरिंग
की,6 की मौत



बैंकॉक,एजेंसी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के पास एक हाई स्कूल में 9वीं कक्षा के छात्र ने शुक्रवार को अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमले में 3 टीचर और 3 छात्रों समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। इनमें दो की हालत गंभीर है।

पुलिस के मुताबिक, घटना नोंथाबुरी प्रांत के डेबसिरिन नोंथाबुरी स्कूल की है। जांच में पता चला कि स्कूल जाने से पहले छात्र ने अपने घर में दादा-दादी की हत्या की थी। बाद में दोनों के शव घर से बरामद हुए।

पुलिस ने बताया कि फायरिंग में इस्तेमाल की गई 9 एमएम पिस्टल छात्र के दादा की थी, जो खुद शिक्षक थे। हमले के बाद आरोपी छात्र भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पटना-एक्सीडेंट में युवक की मौत पर बवाल, 10 गाड़ियां फूंकीं

9 थानों की फोर्स मौके पर



पटना,एजेंसी। पटना में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए। घटना अगमकुआं थाना क्षेत्र के जीरो माइल के पास शुक्रवार सुबह की है, जहां तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने उस बस को आग लगा दी।

फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ ने उसे रोक दिया। इसके बाद हालात और बिगड़ते चले गए। मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन तनाव और बढ़ गया। गुस्साई भीड़ ने 2 पुलिस गाड़ियों, बसों और बाइक समेत करीब 10 वाहनों में आग लगा दी। ट्रैफिक पुलिस पोस्ट जला दी। नेशनल हाईवे-30 पर जाम लगा दिया। पत्रकारों से मारपीट की। मौके पर 9 थानों की पुलिस तैनात की गई है।

उत्तराखंड में बद्रीनाथ-गंगोत्री हाईवे बंद

दिल्ली-एनसीआर में तेज बारिश, सड़कों पर पानी भरा

» नोएडा में एंबुलेंस फंसी
यूपी के 30 गांवों में बाढ़

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली-NCR में दो दिन से तेज बारिश हो रही है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे कई जगह जाम लग गया है। नोएडा के सेक्टर-95 में एक एंबुलेंस पानी में फंस गई।

गुरुवार को द्वाराका सेक्टर-25 में तेज बारिश के दौरान एक युवक खुले नाले में गिरकर तेज बहाव में बह गया। 7 घंटे तक रेस्क्यू अभियान के

बावजूद युवक नहीं मिला। उत्तराखंड में लगातार बारिश से अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी समेत छह नदियां खतरे के स्तर पर बह रही हैं। हरिद्वार-ऋषिकेश में घाट और मंदिर डूब गए हैं। रुद्रप्रयाग में

स्कूल बंद हैं। राज्य की 132 सड़कें और बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। फर्रुखाबाद में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई। 33 गांवों और 40 सरकारी स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस गया। बलिया में एक हफ्ते में 27 घर सरयू नदी में समा चुके हैं।

मानसून अब भी कमजोर, सामान्य से 68 फीसदी कम बारिश: बारिश के बावजूद इस बार नोएडा में मानसून की रफ्तार सामान्य से काफी धीमी बनी हुई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 6 अगस्त तक जिले में केवल 77.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में सामान्य तौर पर करीब 244 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी।

असम: बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हुई... असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। दो और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 97 हो गई है। राज्य के 15 जिलों में 1.68 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि गोलाघाट, शिवसागर और जोरहाट सबसे ज्यादा प्रभावित

यानी अब तक लगभग 68 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होने पर ही इस कमी की कुछ भरपाई हो सकेगी।

पीएम मोदी ने युवाओं से हैंडलूम-डे मनाने की अपील की

40 साल बाद बोफोर्स केस बंद:सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी याचिका खारिज की

● कहा- फ्रेंडशिप डे जैसा उत्साह दिखाएं ● हैंडलूम खरीदें और 'गेट रेडी विद मी' वीडियो बनाएं ● घोटाले के आरोप से राजीव गांधी 1989 का चुनाव हारे थे

नई दिल्ली,एजेंसी। पीएम मोदी ने गुरुवार रात इस्टाग्राम पर देश के युवाओं से हैंडलूम डे पर भारत के हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने की अपील की। पीएम ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे हैंडलूम डे के बारे में बताते नजर आए। साथ ही उन्होंने रथ इस दिन को GRWM ट्रेड यानी गेट रेडी विद मी वीडियो के साथ सेलिब्रेट करने कहा।

पीएम मोदी वीडियो में

खिलाफ देशवासियों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन-जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सभी ने फ्रेंडशिप डे मनाया।

पीएम ने कहा- 'मैं आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। हमें उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से कपड़े बनाते हैं।

पीएम ने कहा- हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें... वीडियो के साथ GRWM वीडियो बनाकर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। हैंडलूम खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इन छोटे-छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना है।'

घरों में लूम पर काम करते हैं। उनके काम को बढ़ावा देना।' मोदी ने के अपील की- 'आइए हम स्वयं दुनिया को भी हो। आइए 7 अगस्त हैंडलूम डे मनाएं।'

दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें। ताकि हमारे बुनकर परिवारों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो। आइए 7 अगस्त हैंडलूम डे मनाएं।'

नई दिल्ली,एजेंसी। करीब 40 साल पुराने बोफोर्स घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आखिरी याचिका भी खारिज कर दी। इसके साथ ही अब यह मामला पूरी तरह खत्म हो गया है।

मौडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस केस में आगे सुनवाई की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने 2005 के दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली अपील भी सुनने से मना

करीब 40 साल पुराने बोफोर्स घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आखिरी याचिका भी खारिज कर दी। इसके साथ ही अब यह मामला पूरी तरह खत्म हो गया है।

मौडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस केस में आगे सुनवाई की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने 2005 के दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली अपील भी सुनने से मना

नई दिल्ली,एजेंसी। यह मामला 1986 में भारत सरकार और स्वीडन की कंपनी एबी बोफोर्स के बीच हुई 1.437 करोड़ रुपए की तोप खरीद डील से जुड़ा है।

दिया गया। घोटाले के आरोप से राजीव गांधी 1989 का चुनाव हार गए थे। इसके बाद यह मामला देश के सबसे बड़े राजनीतिक घोटालों में शामिल हो गया।

सीबीआई का दावा: नीट पेपर लीक साजिश महीनों पहले हुई

एनटीए एक्सपर्ट्स पेपर तैयार करते समय सवाल याद कर लेते थे, छात्रों तक वॉट्सएप-टेलीग्राम से पहुंचा

नई दिल्ली,एजेंसी। NEET-UG 2026 पेपर लीक की साजिश परीक्षा से कई महीने पहले रची गई थी। NTA के एक्सपर्ट्स ने पेपर तैयार करने के दौरान ही सवाल याद कर लिए थे। CBI ने दिल्ली के राजन एवेन्यू कोर्ट में दाखिल 94 पेज की चार्जशीट में यह दावा किया है।

चार्जशीट 28 जुलाई को दाखिल की गई थी। इसकी जानकारी शुक्रवार को सामने आई। इसके मुताबिक, एक्सपर्ट्स NTA ऑफिस से होटल लौटकर याद किए गए सवाल पंक्तियों पर लिखते थे। इसके बाद इन्हें बिचौलियों और कोचिंग नेटवर्क के जरिए छात्रों तक पहुंचाया जाता था।

CBI ने इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें NTA के तीन एक्सपर्ट्स शामिल हैं। आरोप है कि तीनों ने पेपर तैयार

साजिश: महीनों पहले नेटवर्क खड़ा किया... CBI की चार्जशीट में मुताबिक, NEET पेपर लीक किसी एक व्यक्ति की साजिश नहीं थी, बल्कि NTA एक्सपर्ट्स, प्राइवेट कोचिंग संचालकों, बिचौलियों और कुछ छात्रों की मिलीभगत से पूरा नेटवर्क तैयार किया गया था। एजेंसी के अनुसार, परीक्षा से कई महीने पहले ही कोचिंग संचालकों और बिचौलियों ने NTA के तीनों एक्सपर्ट्स से संपर्क साध लिया था। इनके बीच लगातार बातचीत, मुलाकातें और पैसों का लेन-देन हुआ, जिसके जरिए पेपर लीक की पूरी साजिश रची

करने और मॉडरेशन के दौरान अपने पद का दुरुपयोग कर पेपर लीक किए। लीक पेपर टेलीग्राम, वॉट्सएप, PDF और अन्य डिजिटल माध्यमों से भी फैलाए गए।

केंद्र का हलफनामा- एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं

सुप्रीम कोर्ट से कहा- यह सिद्धांत सिर्फ ओबीसी और एसईबीसी पर लागू; याचिकाएं खारिज की जाए

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होता। सरकार ने उन जनहित याचिकाओं (PIL) का विरोध किया है, जिनमें SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने और सरकारी नौकरियों में अधिक न्यायसंगत आरक्षण नीति बनाने की मांग की गई है।

केंद्र ने कहा कि याचिकाओं में मौलिक अधिकार के उल्लंघन का जिक्र नहीं है। साथ ही, मौजूदा कानून में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि क्रीमी लेयर का नियम SC-ST पर लागू होता है। सरकार के मुताबिक, यह अवधारणा सिर्फ

बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इससे आरक्षण का फायदा आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों तक ज्यादा समान रूप से पहुंच सकेगा। याचिकाकर्ताओं ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उप-श्रेणी (सब-कैटेगरी) बनाकर उन्हें प्रवेश और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की भी मांग की है।

केंद्र ने यह भी कहा कि याचिका स्थापित कानून की अनदेखी करती है। सरकार ने इंदिरा साहनी (मंडल आयोग) मामले का हवाला देते हुए कहा कि SC, ST और OBC की पहचान ऐतिहासिक, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर होती है, सिर्फ आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं।

केंद्र ने कहा- सिर्फ संसद को एससी-एसटी सूची में बदलाव का अधिकार... सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा कि SC और ST की सूची में किसी भी तरह का बदलाव केवल संसद ही कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत किसी जाति या जनजाति को सूची में शामिल करने या हटाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है।

सरकार बोली- कल्याणकारी योजनाओं में पहले से आय सीमा लागू: केंद्र ने कहा कि SC, ST और SEBC के लिए चलाई जा रही अधिकांश कल्याणकारी योजनाओं में पहले से आय सीमा लागू है, ताकि योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।

राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला

सीबीआई ने याचिकाकर्ता को पूछताछ के लिए बुलाया

नई दिल्ली,एजेंसी। सीबीआई ने कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप लगाने वाले भाजपा के सदस्य विनेश शिशिर को सोमवार को पेश होने के लिए कहा है।

इस बारे में पूछे जाने पर शिशिर ने बताया कि उन्हें सीबीआई कार्यालय बुलाया गया है। उन्होंने यह कहते हुए कोई और जानकारी देने से इनकार कर दिया कि मामला अभी अदालत में विचारधीन है।

12 मई को हुई थी सुनवाई: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 12 मई को इस मामले में बंद कमेरे में करीब दो घंटे तक सुनवाई की थी। हाई कोर्ट की वेबसाइट पर 14 मई को

दिल्ली,एजेंसी। सीबीआई ने कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप लगाने वाले भाजपा के सदस्य विनेश शिशिर को सोमवार को पेश होने के लिए कहा है।

इस बारे में पूछे जाने पर शिशिर ने बताया कि उन्हें सीबीआई कार्यालय बुलाया गया है। उन्होंने यह कहते हुए कोई और जानकारी देने से इनकार कर दिया कि मामला अभी अदालत में विचारधीन है।

12 मई को हुई थी सुनवाई: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 12 मई को इस मामले में बंद कमेरे में करीब दो घंटे तक सुनवाई की थी। हाई कोर्ट की वेबसाइट पर 14 मई को

शिशिर ने लगाया ये आरोप... शिशिर ने आपराधिक रिट याचिका में गांधी पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता ने आय से अधिक संपत्ति एकत्रित की है। याचिका में इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने का अनुरोध किया गया

सत्यापन किया जा सकता है। पीठ ने सीबीआई और ईडी के अलावा केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफ्आइओ) को भी राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर आठ सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

रानी गार्डन में डीडीए का बुलडोजर एक्शन, 50 अवैध झुगियां और नर्सरी ध्वस्त



नईदिल्ली, एजेंसी। रानी गार्डन में दो दिनों तक डीडीए ने बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बसी 50 झुगियों व नर्सरी को ध्वस्त कर दिया। अवैध रूप से बनी पार्किंग को भी हटा दिया गया है। इस जमीन पर वर्षों से लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। कड़कड़झमा कोर्ट ने इस जमीन पर स्टे लगाया हुआ था। स्टे हटते ही डीडीए ने जिला प्रशासन व दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया। करीब तीन बीघा जमीन को खाली करवाया गया है। डीडीए ने इस जमीन पर अपने विभाग के बोर्ड लगा दिए हैं। एसडीएम गांधी नगर जितेंद्र सिंह ने बताया कि डीडीए की करोड़ों रुपये की जमीन पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था। कड़कड़झमा कोर्ट से स्टे हटते ही डीडीए ने बुधवार व बृहस्पतिवार दो दिनों तक यहां कार्रवाई की। बुलडोजर के जरिये अवैध झुगियों को हटाया। अवैध पार्किंग को हटाया गया। अवैध नर्सरी को भी हटा दिया गया है। जमीन पर जगह-जगह मशीनों की मदद से गद्दे कर दिए हैं। पूरी तरीके से डीडीए ने जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। किसी तरह का विरोध न हो, इसके लिए पुलिस तैनात की गई है। कुछ ही दिनों में डीडीए रानी गार्डन में दूसरी जमीन पर कार्रवाई करेगा।

महाराष्ट्र के 1 लाख से ज्यादा टैक्सी ड्राइवरों ने सीखी कामकाजी मराठी, अब स्थानीय भाषा में करेंगे बात



मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक मई 2026 से सभी टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों के लिए राज्य की आधिकारिक भाषा में बुनियादी दक्षता अनिवार्य किए जाने के बाद अब तक एक लाख से अधिक गैर-मराठी चालकों ने व्यावहारिक मराठी भाषा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। यह जानकारी महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने दी। मंत्रालय में समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सरनाईक ने एप आधारित टैक्सी चालकों समेत अन्य सभी चालकों से 15 अगस्त तक अपना मराठी प्रशिक्षण पूरा करने की अपील की। राज्य सरकार ने अप्रैल में घोषणा की थी कि राज्य में आटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए यात्रियों से मराठी में संवाद करना अनिवार्य होगा। उनके मराठी भाषा ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र दिवस (एक मई) के अवसर पर बालासाहेब ठाकरे मराठी शिकवणी अभियान शुरू किया गया था। इसके तहत प्रवासी चालकों के लिए मराठी भाषा का विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। यह अभियान राज्य के मराठी भाषा विभाग व मुंबई मराठी साहित्य संघ और कोकण मराठी साहित्य परिषद जैसे साहित्यिक निकाय के संयुक्त तत्वावधान में चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभियान को राज्यभर में उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है।

हिमाचल में आफत की बारिश: 145 सड़कें बंद, 224 ट्रांसफार्मर टप; अगले 48 घंटे रहेंगे मुश्किल भरे
शिमला, एजेंसी। हिमाचल प्रदेश में मानसून का प्रकोप लगातार जारी है। बीते 24 घंटों में हुई मुसलाधार वर्षा ने राज्यभर में भारी तबाही मचाई है। मौसम केंद्र शिमला की रिपोर्ट के अनुसार, धर्मशाला में सर्वाधिक 79 मिलीमीटर जोगिंदरनगर में 76, मंडी में 63.4 और राजधानी शिमला में 54.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है।
145 सड़कें यातायात के लिए बंद: 7 अगस्त सुबह 10 बजे तक प्रदेश भर में 145 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो चुकी हैं। मंडी जिले में सबसे अधिक 66 सड़कें प्रभावित हुई हैं, जबकि कुल्लू में 31 और सिरमौर में 28 सड़कें बंद हैं। वर्षा व भूस्खलन के कारण बुनियादी ढांचा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रदेश में 224 बिजली ट्रांसफार्मर टप हैं, जिनमें अकेले मंडी जिले के 182 ट्रांसफार्मर शामिल हैं।

जन्म से मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता पर डोनाल्ड ट्रंप का नया वार्थ बर्थ टूरिज्म रोकने के लिए दो आदेश जारी

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म के आधार पर मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता को सीमित करने और 'बर्थ टूरिज्म' पर रोक लगाने के लिए एक्ुवार को दो नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब कुछ सप्ताह पहले ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर ट्रंप के पहले आदेश को खारिज कर दिया था।क्या है पहला आदेशपहले आदेश का उद्देश्य उन लोगों पर कार्रवाई करना है जो केवल बच्चे को अमेरिका में जन्म दिलाने के लिए वहां आते हैं। इसे 'बर्थ टूरिज्म' कहा जाता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ऐसे लोग पर्यटन वीजा का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उनका असली मकसद बच्चे को अमेरिका में जन्म देकर उसे अमेरिकी नागरिक बनवाना होता है।दूसरे आदेश में क्या हैदूसरे आदेश में उन लोगों की श्रेणियों का दायरा बढ़ाया गया है, जिन्हें जन्म के आधार पर नागरिकता के लिए अयोग्य माना जाएगा। इसमें विदेशी सरकारों के लिए काम करने वाले या उनकी ओर से लॉबींग करने वाले लोगों के बच्चों

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का नया दांव



समेत कुछ अन्य श्रेणियां शामिल की गई हैं।सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश को किया था खारिज30 जून को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के पहले कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा था कि 100 वर्षों से चली आ रही संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग सभी लोगों को अमेरिकी नागरिकता मिलती है।ट्रंप बोले- सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्णओवल ऑफिस में आदेशों पर हस्ताक्षर करने के बाद ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला

दुर्भाग्यपूर्ण था और उनकी सरकार अब उसमें जरूरी बदलाव कर रही है। उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट का जन्मसिद्ध नागरिकता पर फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। इसलिए हम इसमें आवश्यक बदलाव कर रहे हैं।'14वां संशोधन क्या कहता हैअमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन, जिसे 9 जुलाई 1868 को लागू किया गया था, अमेरिका में जन्म लेने या नागरिकता प्राप्त करने वाले सभी लोगों को अमेरिकी नागरिक मानता है। यह प्रावधान गृहयुद्ध के बाद पूर्व गुलामों को नागरिकता देने के लिए

लाया गया था। ट्रंप ने कहा कि यह कानून उस समय की जरूरत के लिए बनाया गया था, लेकिन अब कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाकर 'बर्थ टूरिज्म' का कारोबार चला रहे हैं।क्वाइट हाउस का क्या तर्क हैक्वाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने कहा कि कई लोग पर्यटक बनकर अमेरिका आते हैं, लेकिन उनका असली उद्देश्य बच्चे को अमेरिका में जन्म दिलाना होता है ताकि उसे स्वतः नागरिकता मिल जाए। उनके अनुसार, इससे ऐसे परिवारों को भविष्य में सरकारी योजनाओं, अन्य सुविधाओं और नागरिक अधिकारों तक पहुंच मिल जाती है।किन लोगों के बच्चों पर असर पड़ सकता हैनए आदेश के अनुसार कुछ श्रेणियों के लोगों के बच्चों को नागरिकता संबंधी दस्तावेज देने पर रोक लगाने की बात कही गई है। इनमें शामिल हैं: बर्थ टूरिज्म के जरिए अमेरिका पहुंचने वाले लोगों के बच्चे। आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोगों के बच्चे। विदेशी सरकारों के कर्मचारियों के बच्चे। कुछ अमेरिकी क्षेत्रों में जन्मे ऐसे बच्चे, जहां संघीय कानून के तहत

स्वतः नागरिकता नहीं मिलती।विशेषज्ञों ने बताया असंवैधानिकआवजन कानून के विशेषज्ञों ने राष्ट्रपति ट्रंप के नए आदेशों का विरोध किया है। न्यूयॉर्क के इमिग्रेशन वकील साइरस मेहता ने कहा कि यह आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक लेन-देन जैसी परिभाषा बहुत अस्पष्ट है और इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। वहीं, अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (एसीएलयू) ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि जन्मसिद्ध नागरिकता संविधान द्वारा सुरक्षित अधिकार है। ऐसे में ट्रंप का नया आदेश भी अदालत में टिकना मुश्किल होगा।क्या कहते हैं आंकड़ेमाइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अनुसार, हर साल अमेरिका में 'बर्थ टूरिज्म' के जरिए करीब 22,000 से 26,000 बच्चों का जन्म होने का अनुमान है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2024 में विदेशी पते वाली माताओं से 9,600 बच्चों का जन्म अमेरिका में दर्ज किया गया था।

मेटा को अमेरिकी कोर्ट से बड़ा झटका बच्चों की सुरक्षा में वृक पर 5400 करोड़ चुकाने का आदेश

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने इंस्टाग्राम और फेसबुक की पैंट कंपनी मेटा को उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से युवाओं को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 567 मिलियन डॉलर (करीब 5400 करोड़ रुपये) का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह फैसला उस ऐतिहासिक मुकदमे के दूसरे चरण में आया है, जिसमें मार्च में मेटा को हार का सामना करना पड़ा था। जज ब्रायन बिडशाइड के फैसले के अनुसार, कुल राशि में से 42 करोड़ डॉलर (420 मिलियन डॉलर) युवाओं के इलाज और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। शेष राशि अगले पांच वर्षों में जाारुकता अभियान, रोकथाम कार्यक्रम, स्क्रीनिंग सेवाओं और अन्य संबंधित खर्चों के लिए उपयोग की जाएगी।मुकदमे के पहले चरण में जुरी ने मेटा पर 37.5 करोड़ डॉलर (375 मिलियन डॉलर) का सिविल जुर्माना लगाया था। जुरी ने माना था कि कंपनी को यह जानकारी थी कि उसके प्लेटफॉर्म बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही, कंपनी पर अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी जानकारी छिपाने का भी आरोप माना गया था।क्या अदालत ने मेटा में बड़े बदलाव करने के निर्देश दिएमुकदमे के दूसरे चरण में अभियोजन पक्ष ने अदालत से अनुरोध किया था कि मेटा के प्लेटफॉर्म पर लत पैदा करने वाले फीचर्स को सीमित किया जाए।

कानपुर एक्सप्रेसवे के आउटर रिंग रोड निर्माण में भी बरती गई थी अनदेखी, पीएनसी को मिला था नोटिस

लखनऊ, एजेंसी। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी पीएनसी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को भले ही नान परफार्मर की श्रेणी में डालने को लेकर एनएचएआइ ने मोथं को संस्तुति भेज दी है, लेकिन बीते दो वर्षों पर नजर डालें तो एनएचएआइ इस कंपनी की करतूतों पर लगातार मेहरबान दिखाई देता है। आउटर रिंग रोड की ही बात करें तो अगस्त 2024 में इस लखनऊ आउटर रिंग रोड को बनाते वक्त भी एनएचएआइ ने पीएनसी को नोटिस थमाया था। उस समय कंपनी ने बेहटा गांव से सीतापुर रोड तक (31.74 किमी.) तक फोर लेन सड़क बनाने का काम किया था, जिसमें कई खामियां मिली थीं। तब भी मामला नोटिस तक ही सीमित रह गया और एनएचएआइ ने कार्रवाई को लेकर कुछ भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की। हालांकि सूत्र बताते हैं कि यह नोटिस ऊंचाहार से आने वाली पलाई ऐश को लाने



में पीएनसी के ट्रकों से सड़क खराब होने को लेकर दिया गया था। अब एक बार फिर स्थिति उसी मोड़ पर आ गई है जब कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण में भी पीएनसी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि यह कार्रवाई एक

सप्ताह पहले ही हो चुकी है, जिसे एनएचएआइ लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी गोताम विशाल ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में बताया। उधर पीएनसी ने जवाब देने के लिए समय सीमा बढ़ाने के लिए एनएचएआइ को पत्र लिखा है। एनएचएआइ का खराब सड़क बनाने वाली

कंपनियों से पुराना नाता रहा है। इसमें 105 किमी. आउटर रिंग रोड को बनाने वाली डीआर अग्रवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड सबसे आगे है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के ड्रूम प्रोजेक्टों में शामिल रहे आउटर रिंग रोड को दो साल में बनाना था और डीआर अग्रवाल कंपनी ने साढ़े चार साल लगा दिए थे। एनएचएआइ के तत्कालीन परियोजना निदेशक सौरभ चौरसिया ने विलंब व गुणवत्ता की अनदेखी करने पर डीआर अग्रवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड पर 25 करोड़ का जुर्माना (एलडी यानी लिक्विडिटी डैमेज) लगाया था। इसमें सड़क के निरीक्षण में खामियां मिली थी, इस पर 1.22 करोड़ का अलग से जुर्माना लगाया था। यही नहीं परियोजना निदेशक को निरीक्षण के दौरान सीतापुर रोड से कुर्सी रोड के बीच कई स्थानों पर गड्ढे मिले थे। इसमें तीसरी कंपनी सद्भावना इंजीनियर्स

लि.को भी नोटिस दी गई थी। अब इन सभी कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई चल रही है, इस पर एनएचएआइ चुप्पी साधे हुए है वहीं पीएनसी को एक तरफ नान परफार्मर का नोटिस दिया गया है तो दूसरी तरफ पीएनसी कंपनी अपनी वेबसाइट पर दावा करती है कि उसने मध्यप्रदेश में जावरा-नयागांव का 127 किमी. का फोर लेन, ग्वालियर-भिंड एनएच 92, यूपी में गाजियाबाद-अलीगंज सेक्शन, कानपुर-कबराई सेक्शन, आगरा- ग्वालियर सेक्शन, पंजाब में पानीपत-जालंधर सेक्शन सहित हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेसवे बनाने का अनुभव है। यही नहीं एयरपोर्ट रनवे, ब्रिज निर्माण, पावर सेक्टर में भी कंपनी अभी काम कर रही है। इस संबंध में जब पीएनसी के प्रोजेक्ट मैनेजर वी कुडू से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

चंडीगढ़ में स्मार्ट पार्किंग का देख लो हाल शुल्क पूरा, सुरक्षा जीरो; चोरी हुई तो नगर निगम ने झाड़े हाथ

चंडीगढ़, एजेंसी। शहर में स्मार्ट पार्किंग सिस्टम पर सवाल उठे हैं। आपका वाहन चोरी होता है तो इसके लिए निगम जिम्मेदार नहीं है। नगर निगम पार्किंग शुल्क तो पूरे अधिकार से वसूलता है, लेकिन उसी पार्किंग से वाहन चोरी हो जाए तो उसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। यानी नागरिक पैसे भी दे, वाहन की सुरक्षा का भरोसा भी न मिले और चोरी होने पर नुकसान भी खुद उठाए। वहीं अगर पार्किंग की पर्ची खो जाए तो वाहन मालिक से 100 रुपये जुर्माना वसूला जाता है, लेकिन यदि लाखों रुपये का वाहन पार्किंग से चोरी हो जाए तो निगम लिखित में कह देता है कि इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सवाल यह है कि जब सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं है तो फिर पार्किंग शुल्क आखिर किस बात का लिया जा रहा है।

सुबह पार्किंग में लगाई

एक्टिवा, शाम को गायब मिली: सेक्टर-39 निवासी मोहित गुप्ता ने बताया वह एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं, 23 जुलाई को रोज की तरह अपनी एक्टिवा लेकर सेक्टर-17 पहुंचे। सुबह करीब साढ़े नौ बजे उन्होंने ब्लिंकइट कार्यालय के सामने स्थित नगर निगम की अधिकृत पार्किंग में वाहन खड़ा किया और शुल्क भी जमा किया। शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद लौटे तो पार्किंग से उनकी एक्टिवा गायब थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, पुलिस केवल आवलाइन शिकायत दर्ज कराने की सलाह देकर चली गई। मोहित ने जब पार्किंग संचालक से जवाब मांगा तो उन्हें साफ कह दिया गया कि पार्किंग से वाहन चोरी होने पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। यानी पार्किंग शुल्क लेने वाले हाथ खड़े कर गए और पीड़ित अपने हाल पर छेड़ दिया गया।

नगर निगम का जवाब और भी चौंकाने वाला: पीड़ित ने नगर निगम, उपयुक्त कार्यालय और प्रशासन को लिखित शिकायत देकर मुआवजे की मांग की। नगर निगम ने अपने जवाब में स्पष्ट कर दिया कि पार्किंग में वाहन चोरी होने पर निगम की कोई जवाबदेही नहीं है। वहीं उपयुक्त कार्यालय ने शिकायत संबंधित थाने को भेज दी, जबकि प्रशासन की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यह मामला नगर निगम की पार्किंग नीति पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है।
हर दिन हजारों वाहन, लेकिन सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं: सेक्टर-17 सहित शहर की विभिन्न निगम पार्किंगों में प्रतिदिन हजारों वाहन खड़े होते हैं। लोग यह मानकर शुल्क देते हैं कि उनका वाहन सुरक्षित रहेगा। निगम का जवाब यह संकेत देता है कि

पार्किंग शुल्क केवल वाहन खड़ा करने की कीमत है, उसकी सुरक्षा की नहीं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि पार्किंग परिसर में सीसीटीवी, सुरक्षा कर्मी और शुल्क वसूली के बावजूद वाहन सुरक्षित नहीं है, तो नागरिक आखिर किस भरोसे अपनी गाड़ी वहां खड़ी करें।
सिर्फ वसूली कर रहा एमसी : फॉसवेक: फॉसवेक अध्यक्ष बलजिंदर सिंह बिट्टू का कहना है कि शहर की पेड़ पार्किंग सिर्फ एंटी शुल्क वसूल करने की तरह चल रही है जबकि भीतर वाहन की सुरक्षा के लिए कोई तैनात नहीं होता यहां तक कि वाहन चालकों की मदद के लिए भी कोई कर्मचारी तैनात नहीं होता है। ऐसे में जब सुरक्षा की जिम्मेदारी नगर निगम लेने को तैयार नहीं है तो फिर वसूली किस बात की कर रहा है।

क्या जल्द खत्म होगा पश्चिम एशिया का संघर्ष ट्रंप ने किया बड़ा दावा हथियारों की कमी पर भी बोले

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ शुरू किया गया अभियान बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि मौजूदा युद्ध अब ज्यादा लंबा नहीं चलेगा और उन्हें उम्मीद है कि यह जल्द समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने उन खबरों को भी खारिज किया, जिनमें अमेरिकी सेना के पास जरूरी हथियारों और गोला-बारूद की कमी होने की बात कही जा रही थी।ट्रंप ने युद्ध जल्द खत्म होने का दिया संकेतडोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान शुरू किया था। उनके अनुसार, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ईरान परमाणु हथियार विकसित न कर सके। उन्होंने कहा 'मुझे लगता है कि यह युद्ध बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि यह अब ज्यादा लंबे समय तक चल सकता है।' हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि युद्ध समाप्त करने के लिए आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी।ईरान-ओमान वार्ता पर ट्रंप ने साथी चुप्पीअपने बयान के दौरान ट्रंप ने ईरान और ओमान के बीच जारी बातचीत पर कोई टिप्पणी नहीं की। दितों में ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई थीं,



जिनमें दावा किया गया था। कि अमेरिकी सेना के पास ईरान में युद्ध संचालन और अन्य संभावित सैन्य अभियानों के लिए आवश्यक गोला-बारूद और मिसाइलों की कमी हो रही है। इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना के पास किसी भी महत्वपूर्ण सैन्य अभियान के लिए जरूरी हथियारों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि पैट्रियट मिसाइल, टॉमहॉक मिसाइल, साइडवैंडर मिसाइल और सामान्य गोला-बारूद की मांग जरूर बढ़ी है, लेकिन इन सभी हथियारों का उत्पादन तेज गति से बढ़ाया जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि इन हथियारों के उत्पादन पर आने वाले खर्च को अमेरिकी कांग्रेस को वहन करना होगा।

भुईमाड़ से मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का शुभारंभ, विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याए

हर शुक्रवार गांवों में पहुंचेंगे अधिकारी, योजनाओं का लाभ और शिकायतों का होगा मौके पर समाधान



मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 का शुभारंभ शुक्रवार को कुसमी विकासखंड के ग्राम भुईमाड़ से किया गया शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और प्रशासन को सीधे जनता के बीच ले जाने के उद्देश्य से आयोजित इस अभियान के तहत केशलार,



ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान शासन और जनता के बीच विश्वास का मजबूत माध्यम है उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों तक शासन की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना तथा प्रशासन को गांव-गांव तक पहुंचाना है उन्होंने स्पष्ट किया

कि यदि कोई पात्र व्यक्ति किसी भी योजना के लाभ से वंचित है तो इस अभियान के माध्यम से उसकी समस्या का प्राथमिकता से निराकरण किया जाएगा विधायक ने बताया कि अभियान के अंतर्गत प्रत्येक शुक्रवार अधिकारी अपने कार्यालयों से निकलकर गांवों और शहरी क्षेत्रों में शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित

करना होगा इस अवसर पर जनपद पंचायत कुसमी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। अभियान के दौरान अधिकारियों ने विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र तथा शासकीय उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भुईमाड़ का भी निरीक्षण कर पेयजल, शौचालय, कक्षाओं की स्थिति, विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधार के निर्देश दिए अभियान के शुभारंभ के साथ क्षेत्र में शासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने तथा समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई।

8 अगस्त को सीधी दौरे पर रहेंगे प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल, कई कार्यक्रमों में करेंगे सहभागिता

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं सीधी जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल 8 अगस्त को एक दिवसीय प्रवास पर सीधी आएंगे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे जिले में विभिन्न शासकीय एवं सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रभारी मंत्री जायसवाल दोपहर 12:30 बजे सर्किट हाउस, सीधी पहुंचेंगे। यहां वे जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों तथा आम नागरिकों से मुलाकात कर उनको समझावें एवं सुझावों से अवगत होंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे वे सरस्वती शिशु मंदिर, मड़रिया (सीधी) में आयोजित मेधावी छात्र अलंकरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान करेंगे इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा दोपहर 2 बजे प्रभारी मंत्री सर्किट हाउस में

प्रबंध समिति की बैठक लेंगे। बैठक में विभिन्न विकास कार्यों, योजनाओं की प्रगति तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा किए जाने की संभावना है इसके उपरांत दोपहर 3 बजे वे कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तिरंगा यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे बैठक में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन तथा अन्य आवश्यक तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 3:30 बजे प्रभारी मंत्री स्थानीय कार्यक्रम में भी सहभागिता करेंगे, जहां वे आमजन एवं जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे इसके बाद सायं 5 बजे वे सीधी से बिजुरी (जिला अनूपपुर) के लिए प्रस्थान करेंगे प्रभारी मंत्री के दौर को लेकर जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं संबंधित विभागों के अधिकारियों को कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

15 अगस्त के तिरंगा पतंग मेले को यादगार बनाने जुटा हिन्दू धर्म परिषद, शहर की कई संस्थाओं ने दिया समर्थन



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रीवा शहर में पहली बार आयोजित होने जा रहे तिरंगा पतंग मेला को भव्य और यादगार बनाने के लिए हिन्दू धर्म परिषद ने व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। परिषद के पदाधिकारी शहर के पतंगबाजों, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संगठनों से संपर्क कर उन्हें आयोजन में शामिल होने का आमंत्रण दे रहे हैं यह आयोजन 15 अगस्त को दोपहर 3 बजे ठाकुर रणमत सिंह

महाविद्यालय (टीआरएस कॉलेज) मैदान में आयोजित होगा, जबकि प्रतिभागियों का पंजीयन दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगा पंजीयन पूरी तरह नि:शुल्क रहेगा आयोजन के संयोजक एवं हिन्दू धर्म परिषद के संस्थापक नारायण डिग्वानी, परिषद अध्यक्ष ऋषिशंकर मिश्रा तथा टीआरएस कॉलेज की गर्वनिर्वाह तिवारी अपने साथियों के साथ बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रभक्ति के उत्सव के रूप में मनाना तथा युवाओं और नागरिकों को तिरंगे के

सम्मान से जोड़ना है आयोजन में भाग लेने वाले सभी पतंगबाजों और प्रतिभागियों को विशेष रूप से अहमदाबाद से मंगाई गई तिरंगा पतंगें उपहार स्वरूप प्रदान की जाएंगी। साथ ही उन्हें स्वल्पाहार एवं सम्मान पत्र भी दिए जाएंगे कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी विशेष आकर्षण रहेगा। रिदम म्यूजिकल ग्रुप के अध्यक्ष डॉ. विनोद तिवारी एवं महासचिव पिपुय मिश्रा के मार्गदर्शन में देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी, जिससे पतंगबाजों और उपस्थित नागरिकों में राष्ट्रप्रेम का उत्साह बढ़ेगा। आयोजन को लेकर शहर की कई संस्थाओं ने भी अपना सहयोग देने की घोषणा की है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मोहन तिवारी अपने साथियों के साथ शामिल होंगे वहीं कलम परिवार के अध्यक्ष नागेन्द्र मिश्रा 'मणि' और महासचिव रामकृष्ण द्विवेदी ने देशभक्ति विषयक काव्य पाठ की

जानकारी दी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी मंच के अमनीश शर्मा ने बताया कि मंच के सदस्य तिरंगा झंडों के साथ कार्यक्रम में भाग लेंगे इसके अलावा ब्रह्माकुमारी कला एवं संस्कृति प्रभाग, रीवा के संयोजक बी.के. प्रकाश ने भी अपने सभी सदस्यों के साथ आयोजन को सफल बनाने का भरोसा दिलाया इधर, विन्ध्य काव्य-साहित्य परिषद 'कलम परिवार' ने भी 17 अगस्त को शांतिधाम सभागार में तिरंगा ध्वज वंदना काव्य गोष्ठी आयोजित करने की घोषणा की है इस कार्यक्रम में विंध्य क्षेत्र के साहित्यकार राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रचनाओं का पाठ करेंगे साथ ही वरिष्ठ राष्ट्रभक्त वैद्य बटुक प्रसाद निपाटी के 80वें जन्मदिवस पर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विशेष चर्चा भी होगी आयोजकों का कहना है कि दोनों कार्यक्रमों के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

सीधी में शिक्षा व्यवस्था शर्मसार : 4 महीने में सिर्फ 13 दिन स्कूल आए शिक्षक, फिर भी मिली पूरी 52,800 सैलरी

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले के सिहावल जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम डिट्टली नंबर-4 स्थित प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक दिनेश कोल पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं आरोप है कि शिक्षक शराब के नशे में स्कूल आते थे कक्षा में ही शराब पीते थे और चार महीने में मात्र 13 दिन स्कूल आने के बावजूद उन्हें हर महीने 52,800 का पूरा वेतन जारी किया गया हाल ही में शिक्षक का कक्षा में शराब पीते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आया इसके बाद मौके पर पहुंची मीडिया टीम ने शिक्षक को स्कूल के एक कमरे में दरी बिछकर सोते हुए पाया जगाने पर



वह लड़खड़ाते हुए उठे और बच्चों को पढ़ाने लगे इस दौरान उन्होंने ब्लैकबोर्ड पर सीधी कलेक्टर विकास मिश्रा का नाम भी गलत लिख दिया ग्रामीण ग्यासुद्दीन अंसारी ने आरोप लगाया कि शिक्षक अक्सर जेब में शराब की बोतल लेकर स्कूल आते हैं और बच्चों के सामने ही शराब पीते हैं विद्यालय के बच्चों ने बताया कि

शिक्षक जब भी स्कूल आते हैं, नशे की हालत में रहते हैं। कई बार वे कक्षा में गिर जाते हैं या उल्टी कर देते हैं अभिभावकों का कहना है कि इसी कारण कई परिवारों ने अपने बच्चों का नाम सरकारी स्कूल से कटवाकर निजी स्कूलों में दाखिला करा दिया विद्यालय में पदस्थ दूसरे शिक्षक अशोक कुमार शर्मा के अनुसार, दो वर्ष पहले स्कूल में लगभग 200 छात्र अध्ययनरत थे लेकिन अब यह संख्या घटकर केवल 28 रह गई है। उन्होंने बताया कि उपस्थिति रजिस्टर में दिनेश कोल की चार महीनों में केवल 13 दिन उपस्थिति दर्ज है जबकि संकुल स्तर से उनकी 100 प्रतिशत उपस्थिति भेजी जाती रही जिसके आधार पर उन्हें पूरा वेतन मिलता रहा।

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत रीवा संभाग के कमिश्नर शीलेन्द्र सिंह ने भरतपुर स्थित हथकरघा सहकारी समिति का निरीक्षण कर स्व-सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया इस दौरान कलेक्टर विकास मिश्रा भी मौजूद रहे कमिश्नर ने महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों का अवलोकन किया और उनकी मेहनत, कला एवं कौशल की सराहना की कमिश्नर शीलेन्द्र



सिंह ने कहा कि स्व-सहायता समूह महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम हैं उन्होंने महिलाओं से अपनी आय दोगुनी करने का

लक्ष्य निर्धारित कर योजनाबद्ध ढंग से कार्य करने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, नवाचार और प्रभावी विपणन के

माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाई जा सकती है महिलाओं के हुनर को बाजार से जोड़ना समय की आवश्यकता है जिससे उनकी आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित हो सके निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की प्रभावी मार्केटिंग सुनिश्चित की जाए उन्होंने कहा कि स्थानीय बाजारों के साथ बड़े शहरों और निजी बाजारों की मांग को ध्यान में रखते हुए

उत्पादों की गुणवत्ता, डिजाइन और पैकेजिंग में निरंतर सुधार किया जाए इससे उत्पाद प्रतिस्पर्धी बनेंगे और बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। उन्होंने महिलाओं को केवल शासकीय मेलों और प्रदर्शनियों तक सीमित न रहने की सलाह देते हुए निजी क्षेत्र, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तथा बड़े बाजारों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए प्रेरित किया उन्होंने कहा कि यदि उत्पाद बाजार की मांग के अनुरूप होंगे तो उन्हें व्यापक बाजार, बेहतर पहचान और अधिक आय प्राप्त होगी।

बघोर-मेढ़ौली से मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का शुभारंभ, विधायक विश्वामित्र पाठक बोले- कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं से वंचित न रहे



मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 के तहत शुक्रवार को सिहावल विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मेढ़ौली में संयुक्त जनसंवाद एवं समाधान शिविर का आयोजन किया गया। अभियान के

अंतर्गत ग्राम पंचायत बघोर, मेढ़ौली, गेरुआ एवं तुधमनिया के ग्रामीणों की समस्याओं, मांगों एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए विधायक पाठक ने कहा कि बाद कई प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि शेष

मामलों के समयबद्ध समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का उद्देश्य प्रशासन को जनता के

द्वार तक पहुंचाकर आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना तथा शासन और नागरिकों के बीच विश्वास को और अधिक मजबूत बनाना है उन्होंने कहा कि यह अभियान 8 जनवरी 2027 तक जिले के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संचालित किया जाएगा इसके माध्यम से अधिकारी नियमित रूप से गांवों में पहुंचकर लोगों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी शिकायतों एवं मांगों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करेंगे विधायक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक इसकी जानकारी पहुंचे और कोई भी नागरिक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे उन्होंने कहा

कि शासन की योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य अंतिम पॉइंट में खड़े व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना है इसलिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें और पात्र योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराएं उन्होंने किसानों से जुड़े मुद्दों पर विशेष जोर देते हुए निर्देश दिए कि कृषि सीजन के दौरान किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए। साथ ही भूमिहीन एवं आवासहीन परिवारों को आवासीय भूमि का स्वामित्व दिलाने, पात्र हितग्राहियों के संबल योजना, कर्मकार मंडल पंजीयन तथा आयुष्मान भारत कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों को किसी भी योजना का लाभ पाने में अनावश्यक विलंब या परेशानी नहीं होनी चाहिए। विधायक

विश्वामित्र पाठक ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को जले हुए ट्रांसफार्मरों को शीघ्र बदलने, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा विद्युत संबंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें जिससे शासन की योजनाओं का लाभ समय पर प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंच सके और आमजन का प्रशासन के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हो शिविर के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर ग्रामीणों को आयुष्मान भारत योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्व, कृषि, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा अन्य विभागों की योजनाओं की जानकारी दी गई।

विश्वामित्र पाठक ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को जले हुए ट्रांसफार्मरों को शीघ्र बदलने, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा विद्युत संबंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें जिससे शासन की योजनाओं का लाभ समय पर प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंच सके और आमजन का प्रशासन के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हो शिविर के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर ग्रामीणों को आयुष्मान भारत योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्व, कृषि, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा अन्य विभागों की योजनाओं की जानकारी दी गई।

सीधी वृत्त की समीक्षा बैठक में राजस्व, सीएम हेल्पलाइन, लाइन लॉस और विद्युत चोरी पर दिए सख्त निर्देश

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, रीवा की मुख्य अभियंता प्रमा पांडे ने सीधी वृत्त कार्यालय में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर राजस्व वसूली, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था और उपभोक्ता सेवाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में सीधी वृत्त के सभी कार्यालय प्रमुख, सहायक अभियंता एवं वितरण केंद्र प्रभारी उपस्थित रहे बैठक में मुख्य अभियंता ने राजस्व वसूली, बिलिंग एवं कलेक्शन फिफिशियर्स बढ़ाने, लाइन लॉस कम करने तथा बकाया रशि की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अमिलिया एवं बहरी वितरण केंद्रों में अपेक्षाकृत कम राजस्व वसूली पर नाराजगी जताते हुए निर्धारित लक्ष्य के साथ पिछले माह के बैकलॉग को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए साथ ही गलत बिजली बिलों से संबंधित मामलों का तत्काल निराकरण करने तथा सीआरपीयू सहित सभी प्रदर्शन संकेतकों में सुधार लाने पर विशेष जोर दिया प्रमा पांडे ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 100 दिन से अधिक समय से लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का तीन दिवस के भीतर संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का समयबद्ध समाधान विभाग की प्राथमिकता है इसके साथ ही खराब मीटरों की शीघ्र बदलने, ट्रिपिंग कम करने के लिए आवश्यक रखरखाव कार्य समय पर पूरा करने तथा निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश भी दिए बैठक में विद्युत चोरी के मामलों पर प्रभावी कार्रवाई करने, लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण, नए प्रकरण दर्ज करने तथा कुर्की अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

प्रधानमंत्री मोदी ने उन बच्चों, छात्रों, युवाओं को माफ़ कर दिया है, जिन्होंने उन्हें और उनकी दिवंगत मां को भद्दी-भद्दी गालियां दी थीं। प्रधानमंत्री ने ईसा मसीह और महात्मा बुद्ध के ‘क्षमा-याचना सिद्धांत’ के आधार पर बच्चों को माफ़ किया है। यकीनन उन्हें सद्बुद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा है- ‘मैं उनके आक्रोश को समझता हूं। कुछ शरारती बच्चों ने ये गालियां दी हैं। वे गुमराह हो गए हैं। उन्हें राह पर लाना हमारा ही काम है। बचपन में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे नहीं जानते कि उनका विवेक क्या है। कुछ बेटियों ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, वह भरे लिए एक ‘सांस्कृतिक धक्का’ है। फिर भी बच्चों को सजा देने, अदालतों के चक्कर कटवाने और प्रताड़ित

करने से परिस्थितियां नहीं बदलेंगी।’ बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने गालीबाज युवाओं को तो माफ़ कर दिया, क्योंकि वह देश में ‘जेन-जी’ का मूड भांप चुके थे। हालांकि ये गालीबाज युवा ‘जेन-जी’ के समग्र प्रतिनिधि नहीं हैं और न ही देश का युवा अपने प्रतिनिधि के तौर पर उन्हें स्वीकृति, मान्यता देता है। दिल्ली के ‘जंतर-मंतर’ पर जो युवा-प्रदर्शन किया गया था, उसमें सभी वाकई ‘जेन-जी’ की जमात नहीं थे। उनमें 2873 अपराधिक आरोपित चेहरे भी थे, ऐसा पुलिस ने पहचान कर चिह्नित किया है। उस भीड़ में सपा, ‘आप’, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और वामदलों के भेजे गए काइर भी थे। क्या प्रधानमंत्री उन्हें भी माफ़ कर देंगे, जिन्होंने पुलिस वालों के सिर फोड़ने और किसी भी

कॉंग्रेस अध्यक्ष समेत पार्टी के कई नेता प्रधानमंत्री मोदी के लिए 100 से अधिक अपशब्दों का बार-बार इस्तेमाल करते रहे हैं। यह कौन-सा और कैसा लोकतंत्र है, क्या लोकतंत्र में गालियां देने की भी स्वतंत्रता होती है? प्रधानमंत्री देश के निर्वाचित नेता हैं, न कि उन्होंने यह पद कब्ज़ाया है। उनकी नीतियों, कार्यक्रमों और पूरी सरकार का विरोध करें, शांतिपूर्ण अंदोलन करें, गालियां देने का औचित्य क्या है? उससे तो व्यक्ति का अपना चरित्र कलंकित होता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री के लिए ‘आपतिजनक’ शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं। उन्हें कौन समझ सकता है। वह खुद एक जिम्मेदार, संवैधानिक पद पर बैठे हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री के अधोषित निर्देश

टैक्स की बाधाएं कम करके ही इनोवेशन को बढ़ावा दे सकेंगे

ऑ. अरुणा शर्मा

देश में टैक्सेशन को ‘टैक्स टेररिज्म’ कहा जाने लगा है, खासकर इनोवेशन की दुनिया में। प्रधानमंत्री बार-बार कहते हैं कि भारत का भविष्य महज उपभोक्ता-बाजार बनने में नहीं, तकनीकी क्षेत्र का अगुवा बनने में है। सरकार की ओर से आंत्रिप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए स्टैंड-अप इंडिया और स्टार्ट-अप इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की गई थीं। इससे भारतीय रिसर्चरों को प्रोत्साहन मिला भी, लेकिन सरकारी टैक्स व्यवस्था ने देहां नकारात्मक व्यवधान पैदा कर दिए। तीन उदाहरणों से इसे समझें। पहला मामला एंजेल फंड का है। संभावनाओं वाले स्टार्टअप को निवेशकों ने यह फंड दिया, लेकिन आयकर विभाग ने इसे स्टार्टअप की कमाई मानकर उन्हें नोटिस भेजने शुरू कर दिए। नतीजतन, इनोवेशंस पर ध्यान देने के बजाय छोटे स्टार्टअप को अपनी सीमित मैनपॉवर कानूनी मसलों के समाधान में खपानी पड़ गई। दूसरा मामला आईआईटी संस्थानों का है, जिनके पास सीमित रिसर्च फंड होता है। लेकिन समय के साथ उन्होंने उद्योगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए अलग से इंडस्ट्री फंड भी विकसित कर लिए। इन रिसर्च के निष्कर्षों को लागू करने वाले भी तत्काल मिल जाते थे, क्योंकि समस्या की पहचान और जरूरत का अकालन पहले ही किया जा चुका होता था। फिर एक दिन इन प्रतिष्ठित अकादमिक संस्थानों को जीएसटी के नोटिस मिल गए। इनमें उद्योगों द्वारा वित्तपोषित रिसर्च को सेवा श्रेणी में मान लिया गया। इन दोनों मामलों ने पूरी शोध प्रक्रिया को दो सालों तक बाधित रखा, जब तक कि सरकार ने इन प्रावधानों को वापस नहीं ले लिया। एक दूसरा उदाहरण ऑललाइन गेमिंग उद्योग का है, जहां 2023 में ‘गेम ऑफ़ स्किल’ (जैसा कि विभिन्न अदालती आदेशों में वर्गीकृत किया गया है) पर जीएसटी 18व से बढ़ाकर 28व कर दिया गया। यह टैक्स बढ़ोतरी रेट्रोसेक्टिव प्रभाव से की गई, यानी बड़ा हुआ टैक्स 2017 से लागू किया गया। इस फैसले से पूरा गेमिंग इनोवेशन ठप हो गया। इनोवेशन महज डीआरडीओ जैसे बड़े संस्थानों में ही नहीं होते, बल्कि ये छोटे स्टार्टअप और उनके नवाचार का मिला-जुला परिणाम होते हैं। इन व्यवधानों के चलते भारत ने अपनी बहुत खो दी। यदि भारत को इनोवेशन का हव बनना है और तकनीकी के क्षेत्र में खुद का सामर्थ्य बढ़ाने पर फोकस करना है तो क्या यह जरूरी नहीं कि इन नई उभरती हुई तकनीकों को टैक्स वसूली के नजरिए से परे रखा जाए? जब देश में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित किया गया था तो केंद्र और राज्यों ने दीर्घकालिक नीतियां बनाई और कर रियायतें भी दी थीं। क्या अब फिर वो समय नहीं आ गया, जब इस विषय पर समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाए? दीर्घकालिक, स्थिर, भरोसेमंद और कन्वर्जेंट पॉलिसी फ़्रेमवर्क तैयार किया जाए, ताकि निवेश आकर्षित हो। साथ ही, उन स्टार्टअप को भरोसा मिल सके, जो स्थिर नीतियों वाले देशों का रुख कर रहे हैं। यही प्रक्रिया जारी रही तो भारत की छवि एक ऐसे देश की बन जाएगी, जो महज विदेशों में हो रहे इनोवेशन को ही अपनाता है। आज जरूरत है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों प्रकार के करों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। खासकर तब, जबकि हेल्थ, एजुकेशन सेंस जैसे उपकरण भी लगाए जा रहे हैं। आयकर पर सेंस लगाए जाते हैं। यदि इन माध्यमों से लगातार धन एकत्र हो रहा है, तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। इसका सोशल ऑडिट भी हो। टैक्स से मिलने वाले पैसे को खर्च करते वक्त हमें यह सुनिश्चित करना ही होगा कि बदले में लोगों को किकायती दामों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। भारत के पास तमाम कॉंबिलियते हैं। ज्ञान, प्रतिभा की कमी नहीं है। लेकिन जो चीज इस सब पर पानी फेर देती है, वह है रिसर्च और इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए समग्र दृष्टिकोण का अभाव। यदि हमें विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनना है तो बिना व्यवधान वाले रिसर्च और इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। रिसर्चर्स के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि वे इन झटकों और प्रशासनिक बदलावों से उबर सकें। इस सबसे उनका ध्यान रिसर्च से भटक जाता है। हमें रिसर्च और इनोवेशन का एक स्थिर इको-सिस्टम बनाना ही होगा।

करी से परिस्थितियां नहीं बदलेंगी।’ बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने गालीबाज युवाओं को तो माफ़ कर दिया, क्योंकि वह देश में ‘जेन-जी’ का मूड भांप चुके थे। हालांकि ये गालीबाज युवा ‘जेन-जी’ के समग्र प्रतिनिधि नहीं हैं और न ही देश का युवा अपने प्रतिनिधि के तौर पर उन्हें स्वीकृति, मान्यता देता है। दिल्ली के ‘जंतर-मंतर’ पर जो युवा-प्रदर्शन किया गया था, उसमें सभी वाकई ‘जेन-जी’ की जमात नहीं थे। उनमें 2873 अपराधिक आरोपित चेहरे भी थे, ऐसा पुलिस ने पहचान कर चिह्नित किया है। उस भीड़ में सपा, ‘आप’, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और वामदलों के भेजे गए काइर भी थे। क्या प्रधानमंत्री उन्हें भी माफ़ कर देंगे, जिन्होंने पुलिस वालों के सिर फोड़ने और किसी भी

पीएम की माफी के मायने

तरह संसद भवन में घुसने की साजिशें तैयार की थीं? कुछ छात्रों, बच्चों ने हाथ जोड़ कर प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगी है और अपने अभद्र, अश्लील, अमर्यादित शब्दों के लिए शर्मिंदगी महसूस की है। वह निरंकुश, अपरिमित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 19 (2) में प्रावधान है कि

अभिष्वक्ति की आजादी पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। मसलन-प्रधानमंत्री को

हम पाठकों के लिए एक तथ्य और प्रावधान स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 19 में ‘अभिष्वक्ति की आजादी’ का उल्लेख है, लेकिन अमर्यादित शब्दों के लिए शर्मिंदगी महसूस की है। वह निरंकुश, अपरिमित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 19 (2) में प्रावधान है कि अभिष्वक्ति की आजादी पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। मसलन-प्रधानमंत्री को या किसी को भी इस तरह गालियां देना अभिष्वक्ति की आजादी नहीं है। ‘कॉकरोच’ प्रवक्ता सौरव दास इन गालियों को ‘अपराध’ ही नहीं मानते।

संपादकीय

जजों की संख्या बढ़ाना कितना कारगर

पाती है। अनेक महत्वपूर्ण अपीलों और याचिकाएं महीनों तक सूचीबद्ध होने की प्रतीक्षा करती रहती हैं। अतिरिक्त चार न्यायाधीशों की नियुक्ति से एक साथ अधिक खंडपीठों का गठन संभव होगा। संविधान पीठों पर भी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने का गहरा प्रभाव पड़ेगा। अनेक संवैधानिक और सार्वजनिक महत्व के मामले पांच, सात या नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ के गठन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। न्यायाधीशों की सीमित संख्या के कारण ऐसी पीठें अपेक्षाकृत कम ही गठित हो पाती हैं। अतिरिक्त जज उपलब्ध होने से मुख्य न्यायाधीश नियमित रूप से संविधान पीठों का गठन कर सकेंगे। इससे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों पर शीघ्र निर्णय आएंगे। परिणामस्वरूप कानूनी स्पष्टता बढ़ेगी और अन्य अदालतों को स्पष्ट दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे। उनसे आने वाले

मामलों पर भी इसका प्रभाव होगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में लाखों मामले लंबित हैं। इन न्यायालयों से बड़ी संख्या में अपीलों और विशेष अनुमति याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में देरी होती है तो राज्य स्तर पर भी अनिश्चितता बनी रहती है।अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से इन अपीलों का निस्तारण अधिक तेजी से हो सकेगा। उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध दायर मामलों में शीघ्र अंतिम फैसला आने से राज्यों में न्यायिक प्रक्रिया भी गति पकड़ेगी। इससे नागरिकों को राज्य स्तर से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक न्याय प्राप्त करने में लगने वाला कुल समय कम होगा। आम नागरिकों के जीवन पर इसका प्रभाव सबसे अधिक सार्थक होगा। संपत्ति

विवाद, पारिवारिक मामले, सेवा संबंधी अपीलों, अपराधिक अपीलों तथा मौलिक अधिकारों से जुड़े मुकदमे अब लंबे इंतजार के बजाय अधिक समयबद्ध तरीके से निपट सकेंगे। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए यह बदलाव उनका जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। जो लोग वर्षों से मुकदमेबाजी का खर्च उठाते-उठाते थक चुके हैं, उन्हें राहत मिलेगी। बार-बार अदालत में तारीख पर उपस्थित होने की मजबूरी कम होगी। न्याय अधिक सुलभ, त्वरित और व्यावहारिक प्रतीत होगा। आर्थिक क्षेत्र पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। व्यापारिक विवाद, अनुबंध संबंधी मामले और निवेश से जुड़े मुकदमे लंबे समय तक लंबित रहने से अनिश्चितता बनी रहती है। इसके कारण कंपनियां और उद्यमी अधिक समय संवैधानिक निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। सुप्रीम

पर उन राज्यों की सरकारों और पुलिस ने प्रदर्शनकारी युवाओं के खिलाफ प्राथमिकी और अपराधिक केस वापस लिए हैं या ऐसा निर्णय किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा बच्चों को माफ़ करने की घोषणा की है, क्योंकि वह देश के सर्वप्रथम कार्यकारी प्रमुख हैं, बुजुर्ग हैं, संवैधानिक शक्तियां रखते हैं और एक राजनेता के तौर पर देश की 65 फीसदी से अधिक आबादी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। यहां हम यह भी कहना चाहते हैं कि छात्रों, युवाओं और पुलिस-सुरक्षा बलों के जवानों, अधिकारियों के मानवाधिकार, संवैधानिक अधिकार और नागरिक अधिकार एक समान हैं। युवा चायल हुए हैं, तो यह भी चिंतनीय और निंदनीय है।

जगदीप सिंह

बीते दिनों संसद ने सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया। इसके तहत मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। यह बदलाव केवल पदों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को अधिक तेज, सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस वृद्धि का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव लंबित मामलों के निस्तारण पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज लगभग 92,000 मामले लंबित हैं। वर्तमान में सीमित संख्या में जज होने के कारण प्रतिदिन सीमित मामलों की ही सुनवाई हो

मंदिर प्रबंधक तैयार करने का समय

आडिट, विस्तृत नियमावली और खातों की संपूर्ण जांच जैसी कार्यप्रणाली बने। गणना कक्षों में छेड़छाड़-रोधी प्रणाली, सीसीटीवी, आरएफआइडी टैग युक्त दान-पेटियां और बड़े चढ़ावों के लिए ब्लाकचेन जैसी अपरिवर्तनीय लेखा-प्रणाली ऐसा अनेकशेष मार्ग बना सकती हैं, जिसे कोई दुर्जन आसानी से धोखा नहीं दे सकता। एक अलग संग्रहालय में ऐसे बहुमूल्य चढ़ावों को सीमित अथवा दीर्घकाल के लिए प्रदर्शित भी किया जा सकता है। तृतीय पक्ष लेखा परीक्षण और सरल भाषा में सारांश सहित विस्तृत लेखा रिपोर्टों को हर तिमाही वेबसाइट पर डालने जैसे बहुत से कदम उठाए जा सकते हैं, जो दानदाताओं एवं श्रद्धालुओं में विश्वास का भाव बनाएं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम और गुरुवायूर जैसे कई मंदिरों में ऐसी व्यवस्था बनी भी हुई है। यह भी स्मरण

रहे कि मंदिर न तो कोई ऐसी कंपनी है जो शेयरधारकों के लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करे और न ही वह शासकीय दायित्व का भाग है, जो सरकार के जनकल्याण उद्देश्यों की पूर्ति करे। मंदिर एक जीवंत धार्मिक संस्था है, जिसको वैधता उत्तनी ही मात्रा में अनुष्धानिक शुद्धता, परंपरा और ज्यों का त्यों मंदिरों पर थोपने के बजाय एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जो आडिट, प्रौद्योगिकी, आंतरिक नियंत्रण, पेशेवर वित्त प्रबंधन जैसे आधुनिक प्रशासकीय उपकरणों को आगम शास्त्र और धार्मिक व्यवस्था के अधीन रखे। मंदिर के अपने अनुष्ठानों पर अधिकार का स्रोत आगम शास्त्र शास्त्रीय ग्रंथ हैं, जो विभिन्न संप्रदायों के

मंदिरों के लिए भिन्न प्रकार के प्रविधान निश्चित करते हैं। जैसे वैष्णव मंदिरों के लिए पांड्यरात्र और वैष्णवास आगम, शैव मंदिरों के लिए कामिक, करण और भैरव आगम और शाक्त संप्रदायों के लिए शक्ति आगम। ये कोई आंतरिक प्रमाण प्रचालन प्रक्रियाएं। यानी एसओपी नहीं हैं, जो प्रबंधन की दक्षता को निरूपित करें, बल्कि ये मंदिर का अपना संवैधानिक कानून हैं। यदि किसी सीईओ को धर्मशास्त्रीय प्रशिक्षण के बिना मंदिर संचालन का अधिकार दिया जाए, तो वह भली भंशा के बावजूद प्रतिष्ठित इष्ट के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। वह ऐसे परिवर्तन कर सकता है, जो स्वयं देवता की प्राण-प्रतिष्ठा की पवित्रता को निरस्त कर दे। कुछ इसी प्रकार का दोष सरकारी बोर्डों के मध्ये लगता है, जो परंपराओं की विशिष्टताओं के विपरीत विभिन्न मंदिरों पर एक समान मंदिर-प्रबंधन नियम थोप इस विविधता को रौंद देते हैं। आधुनिक मंदिरों में ऐतिहासिक रूप से सत्ता का एक अंतर्निहित पृथक्करण रहा है। केवल अर्चक या पुजारी ही पुजा-अनुष्ठान कर सकता है। मंदिर वास्तु-संरक्षक, मंदिर की संरचना एवं उसकी शिल्प शास्त्रीय अनुरूपता सुनिश्चित करता है। इसी प्रकार लौकिक ट्रस्टी जो कभी राजा होते थे, मंदिर के भौतिक रखरखाव, भूमि, कोष, सुरक्षा एवं नाम पर मंदिरों की विशाल भौतिक संपत्ति को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए। समाधान वह है, जिसका आदर्श स्वयं आगमों ने सदियों पहले प्रस्तुत किया है। आध्यात्मिक सत्ता की भौतिक प्रशासन से पृथक रखा जाए और प्रशासन को इस प्रकार उत्तरदायी बनाया जाए।

केंद्रीकरण को जन्म दे सकता है। अल्पकालिक अवधि में ऐसे ट्रस्टियों का चयन जो आधुनिक प्रबंधन के साथ आगम शास्त्रों के भी ज्ञाता हों, थोड़ा भैरव आगम और शाक्त संप्रदायों के लिए शक्ति आगम। ये कोई आंतरिक प्रमाण प्रचालन प्रक्रियाएं। यानी एसओपी नहीं हैं, जो प्रबंधन की दक्षता को निरूपित करें, बल्कि ये मंदिर का अपना संवैधानिक कानून हैं। यदि किसी सीईओ को धर्मशास्त्रीय प्रशिक्षण के बिना मंदिर संचालन का अधिकार दिया जाए, तो वह भली भंशा के बावजूद प्रतिष्ठित इष्ट के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। वह ऐसे परिवर्तन कर सकता है, जो स्वयं देवता की प्राण-प्रतिष्ठा की पवित्रता को निरस्त कर दे। कुछ इसी प्रकार का दोष सरकारी बोर्डों के मध्ये लगता है, जो परंपराओं की विशिष्टताओं के विपरीत विभिन्न मंदिरों पर एक समान मंदिर-प्रबंधन नियम थोप इस विविधता को रौंद देते हैं। आधुनिक मंदिरों में ऐतिहासिक रूप से सत्ता का एक अंतर्निहित पृथक्करण रहा है। केवल अर्चक या पुजारी ही पुजा-अनुष्ठान कर सकता है। मंदिर वास्तु-संरक्षक, मंदिर की संरचना एवं उसकी शिल्प शास्त्रीय अनुरूपता सुनिश्चित करता है। इसी प्रकार लौकिक ट्रस्टी जो कभी राजा होते थे, मंदिर के भौतिक रखरखाव, भूमि, कोष, सुरक्षा एवं नाम पर मंदिरों की विशाल भौतिक संपत्ति को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए। समाधान वह है, जिसका आदर्श स्वयं आगमों ने सदियों पहले प्रस्तुत किया है। आध्यात्मिक सत्ता की भौतिक प्रशासन से पृथक रखा जाए और प्रशासन को इस प्रकार उत्तरदायी बनाया जाए।

हम मोर्चे पर नाकाम अमेरिकी राष्ट्रपति

रामिश सिद्दीकी

हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि ईरान पर हमले की पूरी तैयारी है। उसी संदेश में उन्होंने हमला टालने की भी बात कही। इसका कारण यह बताया गया कि ईरान और कई खाड़ी देशों ने इसके लिए आग्रह किया है, क्योंकि समझौते की रूपरेखा बन चुकी है, लेकिन कुछ ही घंटे बाद ईरानी सैन्य सुर्गों के हवाले से खबर आई कि होर्मुज जलमार्ग को खोलने पर कोई सहमति बनी ही नहीं है। इससे कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस ने हमारा के निरस्त्रीकरण का भी पंद्रह सूत्रीय ढांचा घोषित किया था, जबकि उसी दिन अमेरिकी सेंट्रल कमान ने ईरान पर भारी बमबारी कर दी।

कुछ ही दिनों के अंतराल में अमेरिकी सरकार की ये चार घोषणाएं एक गंभीर नीतिगत संकट का संकेत देती हैं। व्यापार हो, गठबंधन हो, महाशक्तियों से संवाद हो या युद्ध-लगभग हर मोर्चे पर अमेरिकी सरकार द्वारा पहले घोषणा की गई और उसे लागू करने वाली व्यवस्था बाद में सामने आई। कई मामलों में तो ऐसी व्यवस्था बन ही नहीं सकी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही दुनिया को यह संदेश दिया था कि वे रूस-यूक्रेन युद्ध को शीघ्र समाप्त करवा देंगे, लेकिन उस घोषणा को भी कई महीने बीत चुके हैं और आज वह युद्ध पहले से अधिक तीव्र हो गया है। जिस युद्ध को समाप्त करने का वादा किया गया था, वह नहीं सका और जिसकी चर्चा भी नहीं थी, वह ईरान युद्ध शुरू हो गया। ट्रंप के मनमाने फैसलों की कीमत वे देना चुका रहे हैं, जिनसे उन्होंने पूछा तक नहीं। दरअसल वाशिंगटन तक पहुंचने में असमर्थ ईरान अब उन्हीं देशों को निशाना बना रहा है, जो उसकी पहुंच में हैं।

खाड़ी के छह देश ईरान से आने वाली मिसाइलों और ड्रोन हमलों का सामना कर रहे हैं। ऊर्जा प्रतिष्ठान और खारे जल के शोधन संयंत्र तक निशाने पर आ चुके हैं। होर्मुज जलमार्ग बंद हो चुका है। इसके कारण ईरान का युद्ध अब केवल क्षेत्रीय नहीं रह गया है। पहले 88 जहाज गुजरते थे, जबकि जुलाई में यह संख्या घटकर मात्र 10 रह गई। इरानी रिगोव्युशनी गाई अब जहाजों की आवाजाही पर शुल्क वसूलने पर आमादा है-प्रति जहाज 20 लाख डॉलर तक, वह भी

युआन, ब्रिटकाइन या अन्य मुद्राओं में। इससे कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हीं जहाजों को सुरक्षा देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन माल के मूल्य का 20 प्रतिशत शुल्क लेकर। इस प्रकार एक ही जलमार्ग पर दो ‘चुंगी नाके’ बन गए हैं और दोनों उन्हीं सरकारों के हैं, जिन्होंने उसे बंद कराया है। दुनिया का लगभग एक-चौथाई समुद्री तेल इसी मार्ग से होकर गुजरता है। इसलिए इसका बोझ केवल खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा है। इसका प्रभाव यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका-हर महाद्वीप

में बीमा, माल-भाड़े और ऊर्जा की बहुतों कीमतों के रूप में दिखाई दिया है। सबसे अधिक बोझ उन्हीं खाड़ी देशों पर पड़ा है, जो इस जलमार्ग के दोनों किनारों पर बसे हैं। यह स्थिति किसी देश की जनता ने नहीं चुनी, लेकिन इसकी कीमत हर देश की जनता चुका रही है। होर्मुज जलमार्ग को दोबारा खोलने के सभी प्रयास अब तक विफल होते दिखाई दे रहे हैं। अब फलस्तिन शांति बोर्ड को इसी पुच्छभूमि में देखिए। वह सफल होगा या नहीं, यह कहना कठिन है, क्योंकि पांच महीनों में उससे केवल

में बीमा, माल-भाड़े और ऊर्जा की बहुतों कीमतों के रूप में दिखाई दिया है। सबसे अधिक बोझ उन्हीं खाड़ी देशों पर पड़ा है, जो इस जलमार्ग के दोनों किनारों पर बसे हैं। यह स्थिति किसी देश की जनता ने नहीं चुनी, लेकिन इसकी कीमत हर देश की जनता चुका रही है। होर्मुज जलमार्ग को दोबारा खोलने के सभी प्रयास अब तक विफल होते दिखाई दे रहे हैं। अब फलस्तिन शांति बोर्ड को इसी पुच्छभूमि में देखिए। वह सफल होगा या नहीं, यह कहना कठिन है, क्योंकि पांच महीनों में उससे केवल

खाड़ी के प्रमुख देशों ने ईरान-अमेरिका संघर्ष को बड़े युद्ध का रूप लेने से रोका है। इसके बावजूद किसी स्थायी समझौते की संभावना अभी दूर दिखाई देती है। ट्रंप का कहना है कि प्रस्तावित सहमति होर्मुज जलमार्ग को स्थायी रूप से खुला रखेगी, जबकि ईरान का कहना है कि किसी भी व्यवस्था में इस जलमार्ग पर उसकी संप्रभुता बनी रहेगी। ये किसी एक समझौते की दो अलग-अलग व्याख्याएं नहीं, बल्कि दो भिन्न समझौते प्रतीत होते हैं। जून में शांति को लेकर दोनों देशों के बीच बनी सहमति भी इसी व्याख्यात्मक मतभेद के कारण टूट गई थी। ट्रंप सरकार की घोषणाओं ने दुनिया को होर्मुज जलमार्ग पर गतिरोध, यूरोप में जारी युद्ध और गाजा में अगुथी शांति दी है। सवाल यह नहीं है कि वाशिंगटन एक और घोषणा कर सकता है या नहीं, बल्कि वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या वह अपनी किसी भी घोषणा को उसके तार्किक और व्यावहारिक परिणाम तक पहुंचा पाएगा या नहीं।

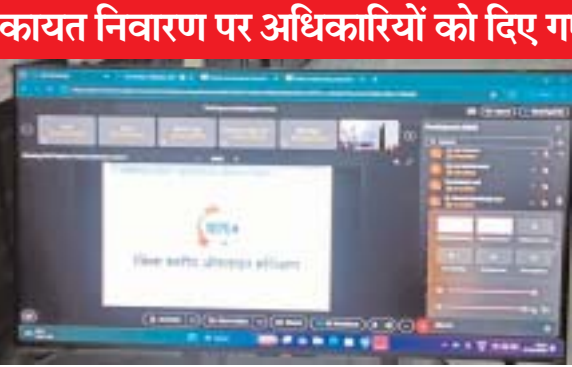
सीएम हेल्पलाइन 1076 के प्रभावी संचालन एवं शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर प्रदेश स्तरीय वर्चुअल प्रशिक्षण सम्पन्न

मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के प्रभावी संचालन शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण तथा पोर्टल के बेहतर उपयोग को लेकर शुक्रवार को प्रदेश स्तरीय वर्चुअल प्रशिक्षण आयोजित किया गया। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष से विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, विभागीय नोडल अधिकारी तथा शिकायतों के निराकरण से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी प्रशिक्षण में शामिल हुए प्रशिक्षण का संचालन मास्टर ट्रेनर अंशुल वर्मा, राकेश गोखल एवं अनुराग दीवान ने किया उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के नवीन प्रावधानों, स्तरवार शिकायत निराकरण, समय-सीमा के पालन, विभागीय समन्वय शिकायत स्थानांतरण स्पेशल क्लोजर, पोर्टल संचालन तथा गुणवत्तापूर्ण निराकरण की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण में बताया गया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 राज्य



शासन की महत्वपूर्ण जन शिकायत निवारण व्यवस्था है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याएं सीधे शासन तक पहुंचा सकते हैं अधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि शिकायतों का उद्देश्य केवल पोर्टल पर जवाब दर्ज करना नहीं बल्कि शिकायतकर्ता की वास्तविक समस्या का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है इसके लिए आवश्यकतानुसार स्थल निरीक्षण, तथ्यात्मक जांच, समाधान के बाद कार्रवाई का विवरण, संबंधित दस्तावेज एवं फोटोग्राफ पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है एल-1 से

एल-4 तक समझाई गई शिकायत निराकरण की प्रक्रिया प्रशिक्षण में शिकायतों के स्तरवार निराकरण की पूरी प्रक्रिया समझाई गई बताया गया कि एल-1 स्तर पर विभागीय अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में शिकायत का परीक्षण एवं निराकरण करेंगे समय पर समाधान नहीं होने अथवा संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में शिकायत क्रमशः एल-2, एल-3 एवं एल-4 स्तर तक पहुंचती है, जहां वरिष्ठ अधिकारी प्रकरण की समीक्षा कर आवश्यक निर्णय लेते हैं। अधिकारियों को यह भी निर्देशित



किया गया कि यदि कोई शिकायत संबंधित विभाग से जुड़ी नहीं है तो उसे लंबित रखने के बजाय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से तत्काल संबंधित विभाग को स्थानांतरित किया जाए, जिससे अनावश्यक विलंब न हो और शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा सके गुणवत्तापूर्ण निराकरण एवं स्पेशल क्लोजर पर विशेष जोर प्रशिक्षण के दौरान शिकायतकर्ता से नियमित संवाद बनाए रखने, आवश्यकता पड़ने पर स्थल निरीक्षण करने तथा समाधान की जानकारी शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराने

पर विशेष बल दिया गया साथ ही यह भी बताया गया कि स्पेशल क्लोजर केवल विशेष परिस्थितियों, जैसे न्यायालय में लंबित प्रकरण, शासन की नीति से जुड़े विषय अथवा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के दायरे से बाहर के मामलों में ही नियमानुसार किया जाएगा पोर्टल संचालन का कराया गया लाइव प्रदर्शन मास्टर ट्रेनरों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल के विभिन्न मॉड्यूल का लाइव प्रदर्शन करते हुए नई शिकायत प्राप्त करने, जांच अधिकारी नियुक्त करने, कार्रवाई दर्ज करने, दस्तावेज एवं फोटो अपलोड करने, शिकायत

स्थानांतरित करने, समय-सीमा की निगरानी करने तथा अंतिम निराकरण तक की संपूर्ण प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। साथ ही डैशबोर्ड के माध्यम से विभागवार प्रदर्शन, लंबित एवं निराकृत शिकायतों की समीक्षा और समय-सीमा विश्लेषण के विभागवार प्रदर्शन, लंबित एवं निराकृत शिकायतों की समीक्षा कर समय-सीमा समाप्त होने से पूर्व उनका गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें प्रशिक्षण के अंत में बताया गया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल के संचालन में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर जिले के ई-डिस्ट्रिक्ट प्रबंधक से संपर्क कर आवश्यक तकनीकी सहायता प्राप्त की जा सकती है, ताकि शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया निर्बाध एवं प्रभावी बनी रहे।

जिले में अब तक 505.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज, चिरमिरी में सर्वाधिक बारिश

मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में इस वर्ष मानसून सक्रिय बना हुआ है जिले में 1 जून से 7 अगस्त 2026 तक कुल 505.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले की विभिन्न तहसीलों में वर्षा का आंकड़ा संतोषजनक रहा है जिससे किसानों को खरीफ फसलों के लिए पर्याप्त नमी मिल रही है जारी आंकड़ों के अनुसार जिले में **सर्वाधिक वर्षा 672.2 मिलीमीटर चिरमिरी तहसील में दर्ज की गई है, जबकि न्यूनतम 391.2 मिलीमीटर वर्षा केलहारी तहसील में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा मनेन्द्रगढ़ तहसील में 639.4 मिमी खड़वावा में 462.0 मिमी भरतपुर में 477.0 मिमी तथा कोटाडोल में 391.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई है प्रशासन के अनुसार मानसून की नियमित गतिविधियों के चलते जिले के अधिकांश क्षेत्रों में जलस्तर में

सुधार हुआ है तालाबों, जलाशयों एवं अन्य जल स्रोतों में भी पानी की उपलब्धता बढ़ी है जिससे पेयजल एवं सिंचाई व्यवस्था को लाभ मिलने की संभावना है वहीं कृषि कार्य भी तेजी से जारी हैं और किसान धान सहित अन्य खरीफ फसलों की खेती में जुटे हुए हैं जिला प्रशासन लगातार वर्षा की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। संबंधित विभागों को आवश्यक सतर्कता बरतने तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि लगातार बारिश के दौरान नदी-नालों एवं जलभराव वाले क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचें तथा मौसम संबंधी जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें जले में अब तक दर्ज हुई औसत वर्षा मानसून की सतर्कता का संकेत मानी जा रही है और आने वाले दिनों में वर्षा का सिलसिला जारी रहने की संभावना के बीच प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ स्थिति की निगरानी कर रहा है।

14 अगस्त को पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा भारत विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस

मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के निर्देशानुसार आगामी 14 अगस्त को पूरे छत्तीसगढ़ में भारत विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जाएगा इस संबंध में राज्य शासन के संस्कृति विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं दिवस का उद्देश्य देश के विभाजनों की ग़मसदी से नई पीढ़ी को परिचित कराना विभाजन से प्रभावित लाखों लोगों के संघर्ष, साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देना तथा राष्ट्रीय एकता अखंडता और सामाजिक सद्भाव की भावना को मजबूत करना है निर्देशों के अनुसार सभी जिलों में भारत विभाजन पर आधारित विशेष प्रदर्शनी व्याख्यान परिचर्चा एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे विभाजन की ग़मसदी की जग गंवांने वाले लोगों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा जाएगा साथ ही मतुआ समुदाय के इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर आधारित लघु वृत्तचित्र का प्रदर्शन भी किया जाएगा विभाजन पीढ़ियों

की स्मृति में कैंडल मार्च तथा विद्यालयों महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा संस्कृति विभाग ने 1 अगस्त से 15 सितंबर 2026 तक MyGov पोर्टल पर आयोजित राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रतियोगिता में अधिक से अधिक युवाओं एवं विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं राज्य स्तर पर भी राज्यपाल अथवा मुख्यमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में स्मृति समारोह आयोजित किया जाएगा इसके साथ ही हर घर तिरंगा एवं वंदे मातरम् अभियान के प्रभावी संचालन के लिए सभी जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी तिरंगा यात्रा रैली, मेला, प्रतियोगिता, सैल्यूटी अभियान, मैराथन और सामूहिक वंदे मातरम् गायन जैसे कार्यक्रमों की नियमित मॉनिटरिंग होगी आयोजन से संबंधित फोटो एवं वीडियो निर्धारित ई-मेल और पोर्टल के माध्यम से संस्कृति विभाग को भेजे जाएंगे।

पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संदेश: क्रीड़ा परिसर लालपुर में लायंस क्लब और ग्रीन वैली क्लब ने किया वृहद वृक्षारोपण



मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। पर्यावरण संरक्षण को जनअदोलन का स्वरूप देने और प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनेन्द्रगढ़ के लालपुर स्थित क्रीड़ा परिसर में लायंस क्लब मनेन्द्रगढ़ एवं ग्रीन वैली क्लब के संयुक्त तत्वावधान में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रेरणादायी आयोजन में क्रीड़ा परिसर के खिलाड़ियों, छात्र-छात्राओं, प्रशिक्षकों तथा क्लब के पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया कार्यक्रम के दौरान क्रीड़ा परिसर के खेल मैदान एवं आसपास के क्षेत्र में फलदार छायादार तथा औषधीय पौधों का रोपण किया गया। छात्र-छात्राओं ने अपनी माताओं के सम्मान में पौधे लगाकर उन्हें प्रकृति से जोड़ने का भावनात्मक संदेश दिया। सभी प्रतिभागियों ने पौधारोपण के साथ-साथ उनके संरक्षण और निष्पक्ष देखभाल का भी संकल्प लिया इस अवसर पर लायंस क्लब एवं ग्रीन वैली क्लब के पदाधिकारियों ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं है बल्कि यह मातृत्व के सम्मान पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संदेश देने वाला अभियान है उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करे तो

धरती को पुनः हरा भरा बनाया जा सकता है ग्रीन वैली क्लब के कोशल अग्रवाल ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वृक्ष पृथ्वी के जीवन का आधार हैं। उन्होंने सभी से अधिक से अधिक पौधे लगाने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया विनोद जायसवाल ने कहा कि पौधारोपण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए उन्होंने कहा कि केवल पौधे लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा और नियमित देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है प्रत्येक नागरिक को अधिक से अधिक लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित करना चाहिए तभी इस अभियान का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा रामचरित द्विवेदी ने अपने माताओं के सम्मान में पौधे लनाकर उन्हें प्रकृति से जोड़ने का भावनात्मक संदेश दिया। सभी प्रतिभागियों ने पौधारोपण के साथ-साथ उनके संरक्षण और निष्पक्ष देखभाल का भी संकल्प लिया इस अवसर पर लायंस क्लब एवं ग्रीन वैली क्लब के पदाधिकारियों ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं है बल्कि यह मातृत्व के सम्मान पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संदेश देने वाला अभियान है उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करे तो

व्हाट्सएप हैक कर ठेकेदार से 1.30 लाख की ठगी पीडब्ल्यूडी के पूर्व एसडीओ बनकर मांगे रुपए

मीडिया ऑडिटर, शिवपुरी (निप्र)। मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के पोहरी में साइबर ठगों ने पीडब्ल्यूडी के सेवानिवृत्त एसडीओ का व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर एक ठेकेदार से 1 लाख 30 हजार रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। आरोपियों ने यूपीआई बंद होने का झंसा देकर परिचित होने का फायदा उठया और अलग-अलग क़िस्तों में रकम अपने खातों में ट्रांसफर करा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है पोहरी की अंसारी कॉलोनी निवासी ठेकेदार उदय सिंह धाकड़ (39) ने पुलिस को बताया कि 28 जुलाई को उनके मोबाइल पर पीडब्ल्यूडी के पूर्व एसडीओ हरिवल्लभ वर्मा के नाम से व्हाट्सएप संदेश आया मैसेज में नेटवर्क समस्या और यूपीआई ब्लॉक होने की बात कहकर एक बारकोड भेजा गया तथा तत्काल एक लाख रुपए की मदद मांगी गई

परिचित का संदेश समझकर ठेकेदार ने पहले 40 हजार फिर 30-30 हजार रुपए बारकोड के माध्यम से भेज दिए बाद में बारकोड की लिमिट समाप्त होने का हवाला देकर एक मोबाइल नंबर पर 30 हजार रुपए और ट्रांसफर करा लिए गए इस तरह कुल 1.30 लाख रुपए की ठगी हो गई कुछ देर बाद परिचितों से व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने की जानकारी मिलने पर पीडित ने तुरंत साइबर सेल और पोहरी थाने में शिकायत दर्ज कराई पुलिस ने आका आरोपी के खिलाफ धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत प्रकरण दर्ज कर बैंक खातों मोबाइल नंबर और डिजिटल ट्रांजेक्शन की जांच शुरू कर दी है विभागीय अधिकारियों के अनुसार हरिवल्लभ वर्मा करीब एक माह पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने की पुष्टि भी सामने आई है।

पहली बार नैनो डीएपी अपनाकर वैज्ञानिक खेती की ओर बढ़े किसान राजमन सिंह ग्राम जरौधा के किसान ने आधुनिक उर्वरक को अपनाया बेहतर उत्पादन और कम लागत की जताई उम्मीद



मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को नैनो उर्वरकों के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है इसका सकारात्मक प्रभाव अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा है मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के विकासखंड खड़वावा अंतर्गत ग्राम जरौधा के किसान राजमन सिंह ने इस खरीफ सीजन में पहली बार अपनी फसल

में नैनो डीएपी का उपयोग करते का निर्णय लिया है। उनका मानना है कि आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि तकनीकों को अपनाकर कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है राजमन सिंह ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से अपनी आवश्यकता अनुसार नैनो डीएपी प्राप्त किया उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष उनके गांव तथा आसपास के कई किसानों ने नैनो डीएपी का उपयोग किया था, जिसके परिणाम काफी उत्साहजनक रहे। फसलों की अच्छी बढ़वार और बेहतर उत्पादन को देखकर उनके मन में भी इस आधुनिक उर्वरक के प्रति विश्वास बढ़ आर उन्होंने इस वर्ष स्वयं इसका उपयोग करते का निर्णय लिया राजमन सिंह ने कहा में पहली बार

नैनो डीएपी का उपयोग कर रहा हूं पिछले साल आसपास के किसानों को इसके अच्छे परिणाम मिले थेउनकी फसल देखकर मुझे भी प्रेरणा मिली मुझे विश्वास है कि इसके उपयोग से मेरी फसल की बढ़वार बेहतर होगी और उत्पादन में भी वृद्धि होगी उन्होंने बताया कि नैनो डीएपी एक बड़ लाभ इसकी आसान परिवहन व्यवस्था भी है पहले पारंपरिक उर्वरकों की भारी बोřियां ढोनी पड़ती थीं जबकि नैनो डीएपी की छोटी बोतल को आसानी से बैग में रखकर घर लाया जा सकता है इससे समय श्रम और परिवहन की लागत तीनों में बचत होती है राजमन सिंह ने अन्य किसानों से भी नई कृषि तकनीकों को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि यदि वैज्ञानिक

सलाह के अनुसार आधुनिक उर्वरकों का सही उपयोग किया जाए तो खेती अधिक लाभकारी और टिकाऊ बन सकती है कृषि विभाग द्वारा जिले में किसानों को नैनो डीएपी सहित आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग के संबंध में लगातार मार्गदर्शन दिया जा रहा है विभाग का उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रेरित करना,उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना तथा कम लागत में अधिक उत्पादन के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है जिले में बढ़ती किसान भागीदारी यह दर्शाती है कि आधुनिक तकनीकों के प्रति किसानों का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है और वे वैज्ञानिक खेती की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

15 अगस्त को जिलेभर में लगेगी उल्लास महा-चौपाल जनभागीदारी से साक्षरता अभियान को मिलेगा विस्तार

मीडिया ऑडिटर, एमसीबी (निप्र)। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2026 को मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में उल्लास-नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत उल्लास महा-चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य समाज में शिक्षा और साक्षरता के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा असाक्षर लोगों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है जिला प्रशासन के अनुसार, यह आयोजन साक्षरता को जन-अभियान का स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होगी। कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय, जनप्रतिनिधि शिक्षक विद्यार्थी, स्वयंसेवक महिला स्व-सहायता समूह और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी रहेगी गांव-गांव और घर-घर तक शिक्षा का संदेश पहुंचाने के लिए विभिन्न

गतिविधियां आयोजित की जाएंगी महा-चौपाल के दौरान शिक्षा के महत्व पर संवाद उल्लास शपथ साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम परिचर्चा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रैली पोस्टर एवं स्तोगन प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा साथ ही नवसाक्षरों और अभियान में योगदान देने वाले स्वयंसेवकों का सम्मान भी किया जाएगा कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों को विशेष रूप से प्रेरित किया जाएगा जो किसी कारणवश शिक्षा से वंचित रह गए हैं ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें उल्लास-नवभारत साक्षरता कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। प्रशासन ने प्रबुद्ध नागरिकों और स्वयंसेवकों से भी इस अभियान में सहयोग कर शिक्षा की अलख जगाने की अपील की है।

भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका: चुनाव याचिका खारिज नहीं होगी, हाईकोर्ट में मेरिट पर चलेगी सुनवाई



मीडिया ऑडिटर, बिलासपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पाटन विधायक भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ झटका लगा है सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने वर्ष 2023 के

विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही निस्त कसे की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि चुनाव याचिका के ट्रयाल के दौरान भूपेश बघेल अपने सभी कानूनी और

तथ्यात्मक तर्क हाईकोर्ट के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र होंगे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुर्यकांत न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई की यह चुनाव याचिका भाजपा नेता एवं दुर्गा संसद विजय बघेल द्वारा दायर की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान से 48 घंटे पहले लागू साइलेंस पीरियड में भूपेश बघेल ने पाटन क्षेत्र में रोड शो और चुनावी गतिविधियां संचालित कर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 का उल्लंघन किया सुनवाई के दौरान भूपेश बघेल की

ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि यदि आरोपों को सही भी मान लिया जाए, तब भी यह केवल धारा 126 के तहत चुनावी अपराध हो सकता है न कि धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण उन्होंने यह भी कहा कि कथित रोड शो का चुनाव परिणाम

पर कोई प्रभाव नहीं पड़, क्योंकि भूपेश बघेल लगभग 20 हजार मतों के अंतर से चुनाव जीते थे सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि रोड शो में सीमित संख्या में लोग शामिल थे और मुख्यमंत्री होने के कारण उनकी सुस्था व्यवस्था स्वाभाविक थी इस पर न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची ने



टिप्पणी की कि कथित उल्लंघन का चुनाव परिणाम पर प्रभाव पड़ या नहीं यह तथ्यात्मक प्रश्न है, जिसका निर्णय साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है अदालत ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी और कहा कि इस मामले की विस्तृत सुनवाई हाईकोर्ट में होगी गौतमलब है कि विजय बघेल ने वर्ष 2024 में दापर चुनाव याचिका में भूपेश बघेल की विधायकी को चुनौती देते हुए आरोप लगाया है कि मतदान से पहले प्रचार प्रतिबंध अवधि के दौरान उन्होंने समर्थकों के साथ रैली एवं रोड शो निकालकर वोट मांगे जो चुनाव कानून का उल्लंघन है।



लंदन,एजेसी। : ऑस्ट्रेलिया के खराब एशेज दौर के बाद टेस्ट टीम से बाहर किए गए इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पोप ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में उनकी वापसी 'पहली बार चुने जाने' जैसा महसूस हो रही है। उनकी नजरें अगले साल घरेलू मैदान पर होने वाली एशेज सीरीज पर हैं और उनका मानना है कि उन्हें अभी भी बहुत कुछ साबित करना है।

इंग्लैंड के लिए लंबे समय तक नंबर तीन पर खेलने वाले पोप को पाकिस्तान के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों के लिए टीम में वापस बुलाया गया है। यह तीन मैचों की घरेलू सीरीज 19 अगस्त से शुरू होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड की 1-4 से हार के दौरान उनका प्रदर्शन

बचपन में उठाए लकड़ियों के गड्ढर, ट्रक ड्राइवरों से लेनी पड़ी लिफ्ट

कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड की हैट्रिक लगातार रचा इतिहास

नई दिल्ली ,एजेसी। कहते हैं कि जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। भारत के महिला वेटफिल्टर मीराबाई चानू शायद इस बात को बखूबी जानती और मानती भी हैं।



कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में तीन गोल्ड मेडल जीतने वाली दुनिया की इकलौती वेटलिफ्टर मीराबाई के लिए जिंदगी कभी आसान नहीं रही, हालांकि उन्होंने हर कदम और हर मोड़ पर संघर्ष का दामन थामे रखा और हर विपरीत परिस्थिति से निकलकर विश्वभर में अपने खेल के दम पर अलग पहचान बनाई। मीराबाई चानू का जन्म 8 अगस्त, 1994 को मणिपुर के इंफाल के पास स्थित नोंगपोक काकाचिंग में हुआ। मीराबाई एक साधारण परिवार से आती थीं, तो आर्थिक तंगी और शुरुआती जीवन संघर्ष से भरा रहा, हालांकि भारतीय महिला वेटलिफ्टर के अंदर बचपन से ही आसाधारण शारीरिक क्षमता थी। वह लकड़ियों के भारी गुट्टर उठाना करती थीं। वह इन गुट्टर को उठाकर पहाड़ियों पर भी चढ़ा करती थीं। मीराबाई के परिवार का किसी भी खेल से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं था, हालांकि बेटी की क्षमता को देखते हुए माता-पिता ने हमेशा मीराबाई को सपोर्ट

किया। मीराबाई की दिलचस्पी पहले तीरंदाजी में थी, लेकिन इंफाल के भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में वेटलिफ्टिंग की ट्रेनिंग को देखकर इस खेल के प्रति मीराबाई की दिलचस्पी बढ़ी। उन्होंने जल्द ही इस खेल में अपना करियर बनाने की ठान ली। घरेलू प्रतियोगिताओं में मीराबाई की प्रतिभा का हर कोई कायल हो गया। मीराबाई ने साल 2008 में मणिपुर स्पोर्ट्स अकादमी में अपनी ट्रेनिंग शुरू की। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें अकादमी तक पहुंचने के लिए रास्ते में बालू और पथर लेकर जाने वाले ट्रक ड्राइवरों से लिफ्ट मांगनी पड़ती थी। नेशनल गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने के बाद मीराबाई चानू ने साल 2014 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना डेब्यू किया। मीराबाई का डेब्यू शानदार रहा और उन्होंने 48 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया, हालांकि यह उनके शानदार करियर की महज शुरुआत मात्र थी। साल 2017 में विश्व वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहीं। वह दो दशकों में यह गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय वेटलिफ्टर बनीं। इसके बाद साल 2018 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला और उन्होंने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। वहीं, 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भी भारतीय महिला वेटलिफ्टर का जलवा देखने को मिला और उन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। वह ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय वेटलिफ्टर बनीं। 2022 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू अपना दबदबा कायम रखने में सफल रहीं और उन्होंने लगातार दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया।

जब हेजलवुड ने पुजारा को गेंदबाजी करने से मना कर दिया था,

भारत के पूर्व बल्लेबाज ने सुनाया किटसा



नई दिल्ली,एजेसी। : भारत के पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ अपने समय के दौरान ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड के साथ हुई एक घटना का जिक्र किया जब मुझे गेंदबाजी करने से मना कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया में 2018/19 और 2020/21 में भारत की यादगार बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज जीत के दौरान हेजलवुड का सामना करते हुए घंटों बिताने के बाद पुजारा ने दृढ़क में एड्स के साथ अपने समय के दौरान हेजलवुड के साथ हुई मजेदार बातचीत को साझा

किया। पुजारा ने जियो हॉटस्टार की सीरीज 'चीकी सिंगल्स' (Cheeky Singles) में कहा, '2018 और 2021 की ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान मैंने जोश हेजलवुड के खिलाफ काफी खेला। फिर मुझे एड्स ने चुन लिया। जब मैं पहली बार नेट्स में बल्लेबाजी करने गया, तो हेजलवुड ने मुझे गेंदबाजी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, 'मैं उसे गेंदबाजी नहीं करूंगा।' हालांकि वह मेरे टीम के साथी थे, फिर भी उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मजाक में कहा कि IPL से पहले के कुछ महीनों में उन्होंने मुझे

'ऐसा लगा जैसे पहली बार टीम में चुना गया हूं



ज्यादा की औसत से सिर्फ 125 रन बनाए थे। नंबर तीन की अपनी जगह जैकब बेथेल को गंवाने के बाद अब वे एक अलग माहौल में वापसी कर रहे हैं। उनके टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और स्टीफन फ्लेमिंग ने ब्रेंडन मैकुलम से कोचिंग की जिम्मेदारी संभाली है। गुरुवार को यह पुष्टि हुई कि विकेटकीपर-बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स नंबर तीन पर बल्लेबाजी करेंगे और डैन लॉरेंस नंबर छह पर स्टोक्स की जगह लेंगे। पोप, जिन्होंने स्टोक्स की गैर-मौजूदगी में पांच टेस्ट मैचों में इंग्लैंड की कप्तानी की थी, अब 64 टेस्ट मैचों के अनुभव के साथ एक उपयोगी खिलाड़ी के तौर पर वापसी कर रहे हैं। उनसे ज्यादा टेस्ट मैच सिर्फ जो रूट ने खेले हैं।

रवींद्र जडेजा का श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में शानदार रिकॉर्ड, आंकड़ों पर डालें नजर

कोलंबो (श्रीलंका),एजेसी। : श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान टीम इंडिया और उसके फैस महान ऑलराउंडरों में से एक, रवींद्र जडेजा को 'लंकन लायंस' (श्रीलंकाई टीम) के खिलाफ खेलते हुए देखेंगे, एक ऐसी टीम जिसके खिलाफ खेलना उन्हें पसंद है। अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच न खेलने के बाद जडेजा श्रीलंका की स्पिन-फ्रेंडली (स्पिनरों के लिए मददगार) परिस्थितियों में वापसी करेंगे। उन्होंने पिछली बार सफेद जर्सी (टेस्ट मैच) में तब खेला था जब भारत को पिछले साल घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के हाथों बुरी तरह हार (व्हाइटवॉश) का सामना करना पड़ा था।

● रविंद्र जडेजा का श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट रिकॉर्ड

जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ 7 टेस्ट मैचों में 9 पारियों में 65.20 की औसत से 326 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 175 रहा है। उन्होंने 23.72 की औसत से 33 विकेट भी लिए हैं, जिसमें दो बार एक पारी में 5 विकेट लेना और 5/41 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन शामिल है। कुल मिलाकर श्रीलंका के खिलाफ 48 इंटरनेशनल मैचों में जडेजा ने 34 पारियों में 46.52 की औसत से 791 रन बनाए हैं (एक शतक और दो अर्धशतक के साथ) और 31.87 की औसत से 66 विकेट भी लिए हैं (दो बार एक पारी में पांच विकेट लेने के साथ)।

टेस्ट टीम में वापसी पर इंग्लैंड के बल्लेबाज ने दिया बयान

टीम से बाहर किए जाने के बाद पोप ने सरे (Surrey) के लिए काउंटी क्रिकेट में कड़ी मेहनत की। उन्होंने 12 पारियों में 56.66 की औसत से 510 रन बनाए, जिसमें एक शतक और चार अर्धशतक शामिल थे। काउंटी में अपने प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए पोप ने कहा, 'काउंटी क्रिकेट में निराशाजनक बात यह थी कि मैं लगभग चार बार 70 के आसपास आउट हुआ (83, 69, 76, 73)। मेरे मन में यह ख्याल आता था कि 'क्या जब दोबारा चयन का समय आएगा तो मैं खुद को कोसूंगा कि मैंने उन पारियों को 150 या 170 रन में क्यों नहीं बदला? पोप ने कहा कि पिछला डेढ़ साल टेस्ट क्रिकेट में उनके लिए 'उत्तार-चढ़ाव भरा' (रोलरकोस्टर जैसा) रहा है। उन्होंने कहा, 'कल का बुलावा ऐसा लगा जैसे पहली बार टीम में चुना गया हूं। मुझे इसकी उम्मीद तो थी, लेकिन पक्का भरोसा नहीं था। हो सकता है कि टीम लिस्ट में मेरा नाम सबसे पहले न हो, लेकिन यह उस मंजिल की ओर एक कदम और बढ़ने जैसा है जहां मैं पहुंचना चाहता हूं।' पोप ने कहा, 'मैंने दुनिया भर में हर जगह खेला है। मुझे अच्छा प्रदर्शन करने का अनुभव है, और मैं जानता हूं कि इन हालात में अच्छा खेलने के लिए मुझे अब क्या करने की जरूरत है। मुझे बस उस सीरीज का इंतजार था जिसमें लगातार शतक पर शतक लगाए जा सकें। जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं बस यह पक्का करना चाहता हूं कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूं।'

- कुल टेस्ट - 7
- इनिंग्स - 9
- औसत - 65.20 की
- रन - 326 रन
- शतक - एक
- अर्धशतक - एक
- सर्वश्रेष्ठ स्कोर - 175
- कुल विकेट - 33
- पारी में 5 विकेट - दो बार
- सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन -

5/41 जडेजा ने 89 टेस्ट मैचों में गेंदबाजी करते हुए 25.11 की औसत से 348 विकेट लिए हैं। उनके नाम 17 बार चार विकेट, 15 बार पांच विकेट और तीन बार दस विकेट लेने का कारनामा दर्ज है, और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/42 रहा है। उन्होंने 133 पारियों में 38.27 की औसत से 4,095 रन भी बनाए हैं, जिसमें 6 शतक और आठ अर्धशतक शामिल हैं। हर गुजरते साल के साथ, बल्ले और गेंद के साथ जडेजा की भरोसेमंदता और बढ़ी है, जिससे वह आधुनिक युग के बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक बन गए हैं।



शुभमन गिल को लगी चोट

श्रीलंका के खिलाफ वॉर्म-अप टेस्ट के पहले दिन मैदान पर नहीं उतरे

कोलंबो,एजेसी। : भारतीय कप्तान शुभमन गिल श्रीलंका क्रिकेट (SLC) XI के खिलाफ तीन दिन के वॉर्म-अप मैच के पहले दिन मैदान पर नहीं उतरेगे। BCCI ने शुक्रवार को बताया कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान उनकी दाहिने हाथ की रिंग फिंगर (अनामिका) में चोट लग गई थी। गिल की गैर-मौजूदगी में SLC XI के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद उप-कप्तान केएल राहुल टीम की कमान संभाल रहे हैं। टॉस के ठीक बाद BCCI ने एक बयान में कहा, 'गुरुवार को भारत की प्रैक्टिस के दौरान कप्तान शुभमन गिल की दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में चोट लग गई थी। एहतियात के तौर पर वह SLC XI के खिलाफ वॉर्म-अप मैच के पहले दिन मैदान पर नहीं उतरेंगे। BCCI की मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रख रही है।' चार दिन से घटाकर तीन दिन का किया गया यह वॉर्म-अप मैच 15 अगस्त से गॉल में श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट

सीरीज से पहले भारत के लिए तैयारी का एक अहम मौका है। भारत ने आखिरी बार जून में टेस्ट क्रिकेट खेला था, इसलिए यह मैच उन्हें श्रीलंकाई हालात (जो मुख्य रूप से स्पिन-फ्रेंडली होते हैं) के अनुकूल ढलने का एक महत्वपूर्ण अवसर देता है। यह मैच शुभदीप घोष के फील्डिंग कोच के तौर पर कार्यकाल की शुरुआत भी है, क्योंकिBCCI ने उनसे पहले इस पद पर रहे टी. दिलीप और असिस्टेंट कोच रयान टेन डेनशेट का कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया था।

जहां बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में मामूली चोट से धीरे-धीरे उबर रहे हैं, वहीं टीम घुटने की चोट के कारण प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बिना खेल रही है। बुमराह की गैर-मौजूदगी के कारण जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को पहली बार टेस्ट टीम में बुलाया गया है।

आर प्रज्ञानानंद ने जीता सेंट लुइस रैपिड और बिल्डर्ज का खिताब



सेंट लुइस,एजेसी। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद ने एक राउंड बाकी रहते हुए ही ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और बिल्डर्ज का खिताब अपने नाम किया। प्रज्ञानानंद और उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव के बीच आखिरी मुकाबले का अंत ड्रॉ पर होने के साथ ही भारतीय ग्रैंडमास्टर का खिताब पक्का हो गया। 20 साल के भारतीय खिलाड़ी ने कुल 35 में से 23 प्वाइंट हासिल करके चैंपियनशिप को अपने नाम किया। शानदार टूर्नामेंट के बाद सिंदारोव ने 22 प्वाइंट के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि वेस्ली सो 20.5 प्वाइंट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। लेबोन अरोनियन 19 प्वाइंट के साथ चौथे स्थान पर रहे, और फैबियानो कारुआना, लीनियर प्रोमिंखेज और जॉर्डन वेन फॉरेस्ट 17 प्वाइंट के साथ संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर रहे। प्रज्ञानानंद को बिना किसी प्लेऑफ के सीधे जीत हासिल करने पर 50,000 अमेरिकी डॉलर और 13 ग्रैंड चेस टूर प्वाइंट मिले। इस नतीजे से प्रज्ञानानंद सिंकफील्ड कप से पहले ग्रैंड चेस टूर स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। हालांकि फैबियानो अभी भी ओवरऑल ग्रैंड चेस टूर स्टैंडिंग में सबसे आगे हैं। प्रज्ञानानंद ने पांच दिन के इस इवेंट में शुरु से आखिर तक बढ़त बनाए रखी। सिंदारोव ने आखिरी दौर में कड़ी चुनौती पैदा की, लेकिन सफल नहीं हो पाए और 1.5 प्वाइंट के अंतर से उपविजेता रहे। जून में, प्रज्ञानानंद प्रतिष्ठित नॉर्वे चैस खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच चुके हैं। सेंट लुइस रैपिड और बिल्डर्ज टूर्नामेंट में 31 जुलाई से 7 अगस्त तक सेंट लुइस चैस क्लब में दस बेहतरीन ग्रैंडमास्टर शामिल हुए। पांच दिनों के खेल में, खिलाड़ियों ने 9 रैपिड राउंड और 18 बिल्डर्ज राउंड खेले। इस दौरान कुल मिलाकर 135 गेम हुए, जिनमें सिंकफील्ड कप और जीसीटी ग्रैंड फाइनल से पहले महत्वपूर्ण टूर प्वाइंट दांव पर थे। इस टूर्नामेंट में दो तेज गति वाले फॉर्मेट शामिल रहे। 9-राउंड का सिंगल राउंड-रॉबिन रैपिड टूर्नामेंट (जो 25 मिनट के टाइम कंट्रोल और पहली चाल से ही 10-सेकंड के इंफोर्मेट के साथ खेला जाता है) और 18-राउंड का डबल राउंड-रॉबिन बिल्डर्ज टूर्नामेंट (जो 5 मिनट के टाइम कंट्रोल और पहली चाल से ही 2-सेकंड के इंफोर्मेट के साथ खेला जाता है)। रैपिड में जीत पर 2 पॉइंट और ड्रॉ पर 1 प्वाइंट मिलता है, जबकि बिल्डर्ज में जीत पर 1 प्वाइंट और ड्रॉ पर 0.5 प्वाइंट मिलता है।



पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा एक्शन

क्रिकेटर पर लगाया दो साल का बैन और 10 लाख जुर्माना



लाहौर,एजेसी। : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने 6 अगस्त 2026 को घरेलू क्रिकेटर हमजा नजर को सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट गतिविधियों से 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया और उन पर 10 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई PCB के जरिए बीजा आवेदन प्रक्रिया के दौरान नजर द्वारा दी गई जानकारी की औपचारिक अनुशासनात्मक जांच के बाद की गई। बोर्ड की आधिकारिक जानकारी के अनुसार जांच में यह पाया गया कि उन्होंने पूरी और सही जानकारी नहीं दी, गुमराह करने वाली जानकारी दी और उस प्रक्रिया के

दौरान जरूरी तथ्यों को छिपाया था।

मामले की जांच के लिए PCB ने तीन सदस्यों का एक पैनल बनाया। पैनल ने सभी उपलब्ध जानकारी की समीक्षा की, नजर का पक्ष सुना और बोर्ड को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें भेजने से पहले उन्हें हर मामले पर अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया। इसके बाद PCB ने उन सिफारिशों के आधार पर अंतिम सजा तय की। तीन सदस्यीय पैनल का मुख्य निष्कर्ष यह था कि PCB के जरिए बीजा आवेदन प्रक्रिया के दौरान नजर ने पारदर्शिता नहीं बरती थी। समिति ने तीन खास कमियां पाईं, उन्होंने पूरी और सही

जानकारी नहीं दी, उन्होंने गुमराह करने वाली जानकारी दी और उन्होंने जरूरी तथ्यों को छिपाया। PCB की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में पुष्टि की गई कि समिति ने सभी उपलब्ध सबूतों की समीक्षा करने और नजर का पक्ष सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपीं। बोर्ड ने खेलने पर बैन और जुर्माना लगाने का अपना फैसला सीधे उसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया।

नजर एक राइट-आर्म ऑफ-ब्रेक बॉलर हैं जो पाकिस्तान के घरेलू सर्किट में खेलते हैं। PCB की आधिकारिक जानकारी में उस खास देश की पुष्टि नहीं की गई है जिसके लिए बीजा आवेदन किया गया था, इसलिए इस रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं किया गया है।

● बैन का क्या मतलब है?

इस सस्पेंशन के कारण नजर पूरे दो साल तक PCB द्वारा मंजूर किसी भी क्रिकेट गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकते। इसमें घरेलू प्रतियोगिताएं और बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आने वाला कोई भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट शामिल है, जिससे बैन खत्म होने तक वे पाकिस्तान में प्रतियर्धी क्रिकेट से बाहर हो जाएंगे। खेलने पर बैन के साथ-साथ 10 लाख PKR का जुर्माना एक अलग सजा है, जो यह हिखाता है कि PCB ने इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया है। यह दोहरी सजा बोर्ड के इस रणनी को दिखाती है कि किसी आधिकारिक प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता की कमी होने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

